

संक्षिप्त डायरी

वार्ड समिति चुनाव के बाद बड़ी हलचल, आप के और पार्श्वों के पार्टी छोड़ने की अटकलें एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की वार्ड समिति चुनाव प्रक्रिया के बाद आम आदमी पार्टी के भीतर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग और उसके परिणामों के बाद ऐसी चर्चाएं तेज हैं कि आने वाले समय में पार्टी के कुछ और पार्श्व भी संगठन से दूरी बना सकते हैं। हालांकि, इन अटकलों के बीच पार्टी नेतृत्व संभावित असंतोष को रोकने और पार्श्वों को एकजुट रखने के प्रयासों में जुट गया है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार अगले वर्ष प्रस्तावित नगर निगम चुनाव को देखते हुए कई पार्श्व अपने राजनीतिक भविष्य का आकलन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कुछ पार्श्व सुरक्षित राजनीतिक विकल्प तलाशने में लगे हैं। वहीं, पार्टी नेतृत्व लगातार पार्श्वों के संपर्क में रहकर संगठन में किसी प्रकार की टूट या असंतोष की स्थिति को रोकने का प्रयास कर रहा है। वार्ड समिति चुनाव से पहले ही क्रॉस वोटिंग की आशंकाएं जताई जा रही थीं। चुनाव परिणाम आने के बाद इन आशंकाओं को बल मिला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी नेतृत्व को संभावित घटनाक्रम का पहले से अनुमान था, लेकिन परिस्थितियों पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रखा जा सका। सूत्रों का कहना है कि रोहिणी क्षेत्र में भी चुनाव परिणामों को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं रहीं। यह भी कहा जा रहा है कि अंतिम समय में राजनीतिक समीकरण बदलने से कुछ स्थानों पर अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नगर निगम से जुड़े पदाधिकारी अपने पार्श्वों के साथ लगातार संवाद बनाए हुए हैं। उनका प्रयास है कि आगामी नगर निगम चुनाव से पहले किसी प्रकार की राजनीतिक टूट की स्थिति उत्पन्न न हो और संगठन को मजबूती के साथ बनाए रखा जा सके। दूसरी ओर राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि यदि आम आदमी पार्टी की स्थिति कमजोर होती है तो इसका लाभ अन्य राजनीतिक दलों, विशेष रूप से कांग्रेस, को मिल सकता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि आने वाले महीनों में दिल्ली की नगर निगम राजनीति में दलों के बीच नए समीकरण बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक पार्श्वों के संभावित इस्तीफों या दल बदल की अटकलों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में फिलहाल यह घटनाक्रम राजनीतिक चर्चाओं और सूत्रों से मिली जानकारी तक सीमित है। आने वाले दिनों में पार्श्वों के रुख और दलों की रणनीति पर दिल्ली नगर निगम की राजनीति की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी।

डूसू चुनाव 2026 को लेकर डीयू प्रॉक्टर टीम और डूसू पदाधिकारियों व छात्र प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित

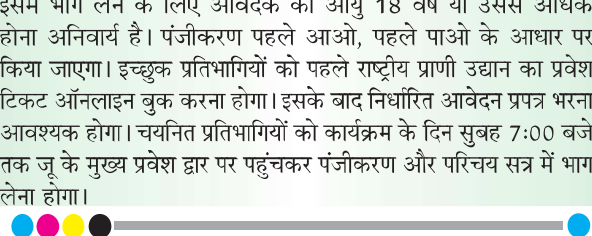
एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (डूसू) चुनाव 2026 को लेकर विश्वविद्यालय प्रॉक्टर और उनकी टीम द्वारा की डूसू पदाधिकारियों और अलग-अलग छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई। प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार, 16 जुलाई को को प्रॉक्टर ऑफिस में आयोजित इस बैठक में दिल्ली हाई कोर्ट और लिंगदोह कमेट्री की गाइडलाइंस के अनुसार, डूसू चुनाव 2026 के संचालन और उससे जुड़े नियमों के बारे में सभी प्रतिनिधियों से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान यह साफ तौर पर तय किया गया कि कैंपस और उसके आस-पास सार्वजनिक संपत्ति को खराब नहीं किया जाएगा और खंभों पर कोई भी होर्डिंग (प्रिटेड और डिजिटल) या बैनर नहीं लगाए या लटकाए जाएंगी। प्रिटेड सामग्री पर पूरी तरह से रोक है। सिर्फ, हाथ से बनी सामग्री ही तय 'वॉल ऑफ़ डेमोक्रेसी' पर लगाने की इजाजत है। दीवारों पर ब्लॉक-प्रिंटिंग या स्पो-पेंटिंग की भी जा सकती। प्रॉक्टर ने बताया कि बैठक के दौरान यह भी साफ कर दिया गया कि एमसीडी के विज्ञापन बोर्ड पर कोई भी फ्लेक्स पोस्टर नहीं लगाया जा सकता। अगर अधिकारियों को ऐसा कोई डिस्टर्बे मिलता है, तो प्रॉक्टर जरूरी कार्रवाई के लिए एमसीडी कमिश्नर को सूचित करेगे। इसके अलावा, किसी भी गाड़ी (जैसे कार, जीप, बस, ऑटो, ई-रिक्शा आदि) पर उम्मीदवार के नाम वाले स्टिकर नहीं लगाए जाएंगे। इस संदर्भ में यह साफ किया गया कि चुनाव प्रचार के दौरान हर उम्मीदवार के लिए सिर्फ, पांच कारों की इजाजत है और ट्रैक्टर, जेसीबी या जानवरों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। टिटेड शीशे वाली या छिपी हुई/बिना नंबर प्लेट वाली कारों पर सख्त रोक है। अगर डीयू कैंपस में कोई अनधिकृत गाड़ी पार्क की जाती है, तो ट्रैफिक पुलिस के नियमों के अनुसार उसका चालान काटा जाएगा या उसे टो उम्मीदवार के नाम वाले कोई भी तोहफे या यादगार चीजें नहीं बांटी जाएंगी। कैंपस में उम्मीदवार के नाम वाले कैैनोपी, छाते आदि लगाने की इजाजत नहीं है। अगर ऐसी कोई सामग्री मिलती है, तो उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा। प्रॉक्टर ने साफ तौर पर कहा कि सार्वजनिक बैठकें करने के लिए पहले से सूचना देना जरूरी है ताकि प्रॉक्टर ऑफिस को जानकारी रहे और कैंपस में किसी भी तरह की अव्यवस्था या जाम से बचा जा सके, साथ ही अलग-अलग छात्र संगठनों की तरीक़ों आपस में न टकराएं। साथ ही, प्रचार के लिए कॉलेजों के अंदर सिर्फ, पाँच विद्यार्थियों को जाने की इजाजत होगी; लड़कियों के कॉलेज हॉस्टल में सिर्फ, लड़कियों को ही जाने की अनुमति होगी। प्रो. मनोज कुमार ने बताया कि इस बातों को लेकर सभी के बीच आपसी सहमति बनी और सभी ने इसके लिए पूरा सहयोग और समर्थन देने का भरोसा दिलाया। यही नियम कॉलेज प्रशासन को भी बताए जाएंगे। प्रॉक्टर ने बताया कि आचार संहिता पहले से ही लागू है।

दिल्ली जू में 'स्पाइडर एंड इंसेक्ट वॉक' का आयोजन, प्रकृति प्रेमियों को मिलेगा अनोखा अनुभव

एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 19 जुलाई को विशेष 'स्पाइडर एंड इंसेक्ट वॉक' आयोजित करने की घोषणा की है। इस प्रकृति भ्रमण के माध्यम से प्रतिभागियों को मकड़ियों, तितलियों और विभिन्न प्रकार के कीटों की अनेकों दुनिया को नजदीक से जानने और समझने का अवसर मिलेगा। जू प्रशासन के अनुसार यह विशेष कार्यक्रम 19 जुलाई, रविवार को सुबह 7:30 बजे से 10:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञ जीव वैज्ञानिक प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें चिड़ियाघर परिसर में प्राकृतिक वातावरण में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों की तितलियों, मकड़ियों और अन्य कीटों का अवलोकन कराया जाएगा। इस दौरान प्रतिभागियों को इन जीवों के व्यवहार, जीवन चक्र, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से दी जाएगी। विशेषज्ञ बताएंगे कि तितलियां प्राकृतिक रूप से फसलों और पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कई कीटों को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं, जबकि अनेक कीट परागण, अपघटन और खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जू प्रशासन ने बताया कि इस विशेष प्रकृति भ्रमण में केवल 20 से 25 प्रतिभागियों को ही शामिल किया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। पंजीकरण पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागियों को पहले राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का प्रवेश टिकट ऑनलाइन बुक करना होगा। इसके बाद निर्धारित आवेदन प्रपत्र भरना आवश्यक होगा। चयनित प्रतिभागियों को कार्यक्रम के दिन सुबह 7:00 बजे तक जू के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचकर पंजीकरण और परिचय सत्र में भाग लेना होगा।



राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने एनडीएमसी की स्वच्छता सेवाओं की समीक्षा की, कर्मचारियों के कल्याण पर दिया जोर

एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में संचालित स्वच्छता सेवाओं और सफाई कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए शून्य मैनुअल स्कैवेंजिंग, कर्मचारियों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम कर्म का समझौता नहीं करने के निर्देश दिए। जव सिंह रोड स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य कर्म सिंह कर्मा ने की। बैठक में एनडीएमसी के सचिव राहुल सिंह, मुख्य अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, सफाई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि, आउटसोर्स एजेंसियों के अधिकारी, ठेकेदार तथा विभिन्न स्वच्छता क्षेत्रों के सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे।

रामलीला आयोजकों को सभी सुविधाएं देगा निगम: संजीव खिरवार



एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली की विभिन्न रामलीला समितियों के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार के नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार से मुलाकात कर रामलीला आयोजन से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। इस दौरान महासंघ की ओर से एक ज्ञापन भी सौंपा गया। अर्जुन कुमार ने आयुक्त से आग्रह किया कि रामलीला मंचन की तैयारियों के लिए नगर निगम के मैदान आयोजकों को कम से कम 40 दिन पहले उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही 25 अगस्त से 25 अक्टूबर तक रामलीला के प्रचार-प्रसार के लिए बैनर और होर्डिंग लगाने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने रामलीला स्थलों पर डीडीटी पाउडर तथा प्लेस्टरिया और डेंगू से बचाव के लिए दवाओं के छिड़काव, अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था तथा पिछले वर्ष की तरह क्षेत्रीय कार्यालयों में एकल छिड़की व्यवस्था लागू करने की मांग भी रखी। महासंघ के महामंत्री सुभाष गोयल ने बताया कि इस वर्ष रामलीला मंचन समारोह 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक आयोजित होगा, जबकि राश्वरा पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि दिल्ली की सभी रामलीलाओं को नगर निगम का पूरा सहयोग मिलेगा और आयोजन को सफल बनाने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

बीएलओ पूरी मेहनत से कर रहे हैं कार्य: श्याम सुन्दर अग्रवाल

एजेंसी

नई दिल्ली। पूर्व महापौर श्याम सुन्दर अग्रवाल ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में लगे बृथ स्तर अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि वे कड़ी धूप के बीच घर-घर जाकर पूरी लगन और मेहनत से अपना दायित्व निभा रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से अधिकारियों का सहयोग करने की अपील की। श्याम सुन्दर अग्रवाल ने बताया कि उनके कार्यालय में बृथ स्तर अधिकारी कविता जैन उनके और उनके परिवार के प्रपन्न प्राप्त किए। इस दौरान अधिकारियों ने घर-घर जाकर पुनरीक्षण कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर लोगों का



व्यवहार सहयोगात्मक नहीं होता, जबकि अनेक मतदाता सम्मानपूर्वक उनका स्वागत भी करते हैं। कविता जैन ने बताया कि अब तक लगभग 200 प्रपत्र एकत्र किए जा चुके हैं और निर्धारित लक्ष्य शीघ्र पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के सहयोग से पुनरीक्षण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्याम सुन्दर अग्रवाल ने सभी



कर्म सिंह कर्मा ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहरों के वास्तविक संरक्षक हैं, जो प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने दायित्वों का निर्वहन कर नागरिकों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान सफाई कर्मचारी संगठनों और यूनियनों के प्रतिनिधियों से विस्तार से चर्चा की गई। कर्मचारियों द्वारा उठाई गई समस्याओं, शिकायतों और सुझावों से एनडीएमसी प्रशासन को अवगत कराया गया है तथा आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया

व्यवस्थाओं से जुड़े सभी अभिलेख नियमित रूप से उपलब्ध कराने और अद्यतन रखने के निर्देश भी दिए गए। कर्म सिंह कर्मा ने कहा कि प्रत्येक सफाई कर्मचारी को कानून के तहत मिलने वाले सभी अधिकार और सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की गरिमा, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, सीवर और नालों के रखरखाव, अभियांत्रिकी कार्य, टोस अपशिष्ट प्रबंधन, कर्मचारी कल्याण, स्थापना, अनुबंध तथा श्रम कानूनों के अनुपालन से जुड़े विभागों की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिन पर विस्तार से चर्चा की गई।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी, प्रभावी निगरानी व्यवस्था और कर्मचारी कल्याणकारी उपायों के माध्यम से विश्वस्तरीय स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराना समय की आवश्यकता है।

भारी बारिश से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत, 33.31 करोड़ रुपये की सहायता राशि मंजूर

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2025 में भारी बारिश और जलभराव से फसलों पूरी तरह नष्ट होने वाले किसानों को राहत देने के लिए 33.31 करोड़ रुपये से अधिक की अनुग्रह सहायता राशि को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय के तहत पात्र किसानों को 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने राजस्व विभाग और जिलाधिकारियों को राहत राशि के वितरण की प्रक्रिया बिना किसी विलंब के शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के अनुसार अगस्त और सितंबर 2025 में हुई अत्यधिक वर्षा के कारण दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई थीं। प्रभावित किसानों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से यह सहायता राशि स्वीकृत की गई है। योजना के अंतर्गत दिल्ली के विभिन्न जिलों और उपमंडलों में फैले कुल 4,442.41 हेक्टेयर



प्रभावित कृषि क्षेत्र को शामिल किया गया है। सहायता राशि अगले महीने से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार किसानों के हर सुख-दुख में उनके साथ खड़ी है। प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को जो आर्थिक क्षति हुई है, उसकी भरपाई पूरी तरह संभव नहीं है, लेकिन यह सहायता उनके नुकसान को कम करने का एक प्रयास है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र किसानों को समय पर राहत

शीश महल को भ्रष्टाचार का स्मारक बनाया जाए: देवेन्द्र यादव

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के सरकारी आवास के रूप में चर्चित शीश महल को विलासिता आधारित आरिथ्य केंद्र में बदलने के बजाय भ्रष्टाचार का स्मारक बनाया जाना चाहिए, ताकि जनता के सामने कथित वित्तीय अनियमितताओं का उदाहरण रखा जा सके। देवेन्द्र यादव ने कहा कि करदाताओं के धन से तैयार किए गए इस भवन का उपयोग सार्वजनिक हित से जुड़े सेवा केंद्र के रूप में किया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि आम जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकारी धन का किस प्रकार उपयोग किया गया। उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदन का हवाला देते हुए दावा किया कि बंगले के विस्तार और नवीनीकरण पर 33.66 करोड़ रुपये खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही तत्कालीन उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना के समक्ष मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं और अत्यधिक व्यय की शिकायत दर्ज कराई थी। देवेन्द्र यादव ने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग शीश महल को किसी विलासिता आधारित आरिथ्य संचालक को पट्टे पर देने की योजना बना रहा है। उनके अनुसार ऐसा करने से भवन पर हुए कथित खर्च और उससे जुड़े विवादों को दबाने का प्रयास हो सकता है। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की शिकायत के बाद ही भवन में निर्माण कार्य रोक़ा गया था और मामले की जांच प्रारंभ हुई थी। उनके अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सहित विभिन्न एजेंसियों ने जांच शुरू की थी, लेकिन वर्तमान सरकार की उदासीनता के कारण मामले में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है।



जनता के सामने कथित वित्तीय अनियमितताओं का उदाहरण रखा जा सके। देवेन्द्र यादव ने कहा कि करदाताओं के धन से तैयार किए गए इस भवन का उपयोग सार्वजनिक हित से जुड़े सेवा केंद्र के रूप में किया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि आम जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकारी धन का किस प्रकार उपयोग किया गया। उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदन का हवाला देते हुए दावा किया कि बंगले के विस्तार और नवीनीकरण पर 33.66 करोड़ रुपये खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही तत्कालीन उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना के समक्ष मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं और अत्यधिक व्यय की शिकायत दर्ज कराई थी। देवेन्द्र यादव ने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग शीश महल को किसी विलासिता आधारित आरिथ्य संचालक को पट्टे पर देने की योजना बना रहा है। उनके अनुसार ऐसा करने से भवन पर हुए कथित खर्च और उससे जुड़े विवादों को दबाने का प्रयास हो सकता है। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की शिकायत के बाद ही भवन में निर्माण कार्य रोक़ा गया था और मामले की जांच प्रारंभ हुई थी। उनके अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सहित विभिन्न एजेंसियों ने जांच शुरू की थी, लेकिन वर्तमान सरकार की उदासीनता के कारण मामले में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है।

राजस्थान में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक, दो सप्ताह तक नहीं होगी ध्वस्तीकरण कार्रवाई

एजेंसी

नई दिल्ली। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों, मकानों तथा अन्य निर्माणों के विरुद्ध चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए संबंधित संपत्तियों पर 2 सप्ताह तक किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अपने संवैधानिक और विधिक तर्कों के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय को जोधपुर खंडपीठ का रुख करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से लगभग 40 प्रभावित व्यक्तियों के पक्ष में दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। मामले को सुनवाई न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मकानों, मस्जिदों, मदरसों और अन्य संपत्तियों के विरुद्ध लगातार ध्वस्तीकरण को कार्रवाई की जा रही है तथा बड़ी संख्या में धार्मिक और आवासीय संपत्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने दलील दी कि किसी भी नागरिक या धार्मिक स्थल के विरुद्ध कार्रवाई संविधान, विधि और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप ही की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि तत्काल अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया तो प्रभावित लोगों को अप्रूपीय क्षति हो सकती है। जमीयत



राशि उपलब्ध कराई जाए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संपन्न हो। सरकार द्वारा जारी विवरण के अनुसार अलीपुर (नरैला) के 364.74 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र के लिए 2.74 करोड़ रुपये, बुराड़ी के 17.33 हेक्टेयर के लिए 13 लाख रुपये, पंजाबी बाग (मुंडका) के 51.50 हेक्टेयर के लिए 38.63 लाख रुपये तथा विकासपुरी के 26.55 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 19.92 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार कंझावाला क्षेत्र के अंतर्गत मुंडका और बवाना में

कुल 1,758.76 हेक्टेयर प्रभावित कृषि भूमि के लिए क्रमशः 8.70 करोड़ रुपये और 4.49 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। रोहिणी (मुंडका) के 137.59 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 1.03 करोड़ रुपये, कापसहेड़ा (मंटियाला) के 625.93 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 4.69 करोड़ रुपये तथा नजफगढ़ और मंटियाला के अंतर्गत कुल 1,459.97 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र के लिए क्रमशः 9.98 करोड़ रुपये और 96.74 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र किसानों को ही मिलेगा। इसके लिए स्पष्ट पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। सहायता राशि केवल उन किसानों को प्रदान की जाएगी जो संबंधित भूमि के पंजीकृत अथवा अभिलेखित स्वामी हैं और जिनकी फसल अगस्त-सितंबर 2025 की भारी वर्षा एवं जलभराव के कारण पूरी तरह नष्ट हुई थी।

राजस्थान में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक, दो सप्ताह तक नहीं होगी ध्वस्तीकरण कार्रवाई

एजेंसी

नई दिल्ली। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों, मकानों तथा अन्य निर्माणों के विरुद्ध चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए संबंधित संपत्तियों पर 2 सप्ताह तक किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अपने संवैधानिक और विधिक तर्कों के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय को जोधपुर खंडपीठ का रुख करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से लगभग 40 प्रभावित व्यक्तियों के पक्ष में दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। मामले को सुनवाई न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मकानों, मस्जिदों, मदरसों और अन्य संपत्तियों के विरुद्ध लगातार ध्वस्तीकरण को कार्रवाई की जा रही है तथा बड़ी संख्या में धार्मिक और आवासीय संपत्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने दलील दी कि किसी भी नागरिक या धार्मिक स्थल के विरुद्ध कार्रवाई संविधान, विधि और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप ही की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि तत्काल अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया तो प्रभावित लोगों को अप्रूपीय क्षति हो सकती है। जमीयत



उलेमा-ए-हिंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी, निजाम पाशा, तालिह हक़ीम तथा अधिवक्ता मंसूर अली खान ने दवाहों, मकानों तथा अन्य निर्माणों के विरुद्ध चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए संबंधित संपत्तियों पर 2 सप्ताह तक किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अपने संवैधानिक और विधिक तर्कों के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय को जोधपुर खंडपीठ का रुख करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से लगभग 40 प्रभावित व्यक्तियों के पक्ष में दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। मामले को सुनवाई न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मकानों, मस्जिदों, मदरसों और अन्य संपत्तियों के विरुद्ध लगातार ध्वस्तीकरण को कार्रवाई की जा रही है तथा बड़ी संख्या में धार्मिक और आवासीय संपत्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने दलील दी कि किसी भी नागरिक या धार्मिक स्थल के विरुद्ध कार्रवाई संविधान, विधि और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप ही की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि तत्काल अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया तो प्रभावित लोगों को अप्रूपीय क्षति हो सकती है। जमीयत

उलेमा-ए-हिंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी, निजाम पाशा, तालिह हक़ीम तथा अधिवक्ता मंसूर अली खान ने दवाहों, मकानों तथा अन्य निर्माणों के विरुद्ध चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए संबंधित संपत्तियों पर 2 सप्ताह तक किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अपने संवैधानिक और विधिक तर्कों के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय को जोधपुर खंडपीठ का रुख करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से लगभग 40 प्रभावित व्यक्तियों के पक्ष में दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। मामले को सुनवाई न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मकानों, मस्जिदों, मदरसों और अन्य संपत्तियों के विरुद्ध लगातार ध्वस्तीकरण को कार्रवाई की जा रही है तथा बड़ी संख्या में धार्मिक और आवासीय संपत्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने दलील दी कि किसी भी नागरिक या धार्मिक स्थल के विरुद्ध कार्रवाई संविधान, विधि और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप ही की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि तत्काल अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया तो प्रभावित लोगों को अप्रूपीय क्षति हो सकती है। जमीयत

संपत्ति के संचय से अधिक महान कार्य है उसका समाज हित में समर्पण: प्रो. योगेश सिंह



विश्वविद्यालय के मध्य सार्थक सहभागिता को सुदृढ़ करने की दिशा में दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। कार्यक्रम के समापन पर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के

अधिष्ठाता प्रो. ए. वेंकटरमन द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने विश्वविद्यालय नेतृत्व की दूरदृष्टि एवं समाज के व्यापक हित के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को सराहना करते हुए।



संक्षिप्त समाचार

इयूटी से लौट रही नर्स की सड़क हादसे में मौत

गोरखपुर, एजेंसी। बेलीपार थाना क्षेत्र के भीवापार निवासी 22 वर्षीय नर्स प्रेरणा गौड़ की बृहस्पतिवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। गोरखपुर के एक निजी अस्पताल से इयूटी कर घर लौटते समय अमरुद मंडी के पास अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी में पीछे से टक्कर मार दी। घायलावस्था में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पराग गौड़ की बेटी प्रेरणा बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे अस्पताल से इयूटी कर घर लौट रही थीं तभी यह घटना हुई। घटना के बाद चालक वाहन लेकर भाग गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। प्रेरणा पांच भाई-बहनों में सबसे बड़ी थीं। उनके पिता पराग गौड़ बंगलूरु में पेंट-पॉलिश का काम करते हैं। वह इन दिनों घर आए हुए हैं। प्रेरणा पिछले तीन वर्षों से एक निजी अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत थीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।

जयंती पर कैलाश प्रकाश को दी श्रद्धांजलि

मेरठ , एजेंसी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में शुक्रवार को विश्वविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय कैलाश प्रकाश की जयंती मनाई गई। इसमें उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शिक्षा, समाज, चिकित्सा सहित अन्य क्षेत्रों में उनके योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इतिहास विभागाध्यक्ष प्रो. कृष्णकांत शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि कैलाश प्रकाश ने अपना संपूर्ण जीवन समाज और शिक्षा के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना में भी स्व. कैलाश प्रकाश का योगदान अमूल्य है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और अथक प्रयासों के कारण मेरठ को उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनने का गौरव प्राप्त हुआ। आराधना ने कैलाश प्रकाश के जीवन को युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया। प्रो. एवी कौर ने कहा कि ऐसे महान व्यक्तित्वों के आदर्श समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं। वहीं प्रो. विघ्नेश कुमार ने कहा कि कैलाश प्रकाश ने शिक्षा, सामाजिक विकास और खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देकर मेरठ सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाई। उनका जीवन त्याग, सेवा और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है।

मुस्तफिजुल के भागे साथी की तलाश में जुटी एसटीएफ

गोरखपुर , एजेंसी। एक लाख रुपये के इनामी बदमाश मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद अब एसटीएफ की जांच उसके भागे साथी की तलाश पर केंद्रित हो गई है। रामनगर–कड़जहां फोरलेन पर हुई मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले बदमाश की पहचान और तलाश के लिए एसटीएफ तकनीकी साक्ष्यों का सहारा ले रही है। एसटीएफ की टीम सीसीटीवी कैमरा फुटेज, सर्विलांस और मोबाइल नेटवर्क की मदद से भागे बदमाश तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि मुस्तफिजुल अपने साथी के साथ गोरखपुर किस मकसद से आया था और उसके निशाने पर कौन था। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक, जांच में आजमगढ़ के एक नेता की हत्या की साजिश का एंगल भी सामने आया है। इसी इनपुट के आधार पर टीम ने बदमाशों की घेराबंदी की थी। मुठभेड़ में मुस्तफिजुल रहमान मारा गया जबकि उसका साथी मौका पाकर भाग गया। 13 जुलाई की रात करीब 11 बजे रामनगर–कड़जहां फोरलेन पर हुई मुठभेड़ के दौरान मुस्तफिजुल का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर भाग निकला था।

नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत की शक्त नींव

गोरखपुर , एजेंसी। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर (एमजीयूजी) में भारत सरकार के युवा गौरवक एवं खेल मंत्रालय के निर्देशों के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में ‘विकसित भारत युथ कनेक्ट कार्यक्रम’ का आयोजन किया गया। ‘नशा मुक्त युवा–विकसित भारत’ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एवं युथ आइकन प्रियांशु भारद्वाज ने कहा कि नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत की शक्ति नींव है। प्रियांशु भारद्वाज ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब देश का युवा नशामुक्त, स्वस्थ, शिक्षित एवं जागरूक होगा। नशा युवाओं की प्रतिभा, आत्मविश्वास और भविष्य को कमजोर करता है। उन्होंने युवाओं से डिजिटल साक्षरता, सामाजिक सेवा, न्याचार तथा राष्ट्रहित के कार्यों में बढ़–चढ़कर भाग लेने का आह्वाण किया। विश्वविद्यालय के नशामुक्ति अभियान के नोडल अधिकारी डॉ. दिलीप मिश्रा ने कहा कि कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। डॉ. अशोक कुमार वर्मा व इंजीनियर उदयभान यादव ने कहा कि प्रतिस्पर्धा और मानसिक दबाव के कारण नशे युवा गंतत आदतों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. धनंजय पांडेय, कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अमित उपाध्याय, अनिल कुमार पटेल, डॉ. रवि निषाद, साध्वी नंदन पांडेय, विकास कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।

गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव भी खेल में शामिल

लखनऊ, एजेंसी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की विस्तृत जांच में ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा और गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव की मुख्य भूमिका बताई गई है। अनिल की सलिप्तता होने की ओर इशारा किया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अनिल पर भी कानूनी शिकंजा कसना लगभग तय है। सुभाष पहले से ही जेल में बंद है।

सूत्रों के मुताबिक, विस्तृत जांच में एसआईटी ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका खंगाली। जिसमें अनिल मिश्रा की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। उसके पुछ्छा साक्ष्य है। वहीं, इस बात की भी पुष्टि हुई है

कई नाम एफआईआर में बढ़ेंगे

एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उसी में टिन्त्र यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प, लवकुश, मनीष, अविनाश, करुणेश और रमाशंकर की भूमिका का जिक्र था। इसलिए ये सभी आरोपी बनाए गए थे। अनिल के नाम का भी जिक्र था, लेकिन एफआईआर में उनको शामिल नहीं किया गया था। अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। सूत्र बताते हैं कि अब एसआईटी की विस्तृत जांच के बाद अज्ञात में कई नाम खुल सकते हैं। इसमें अनिल मिश्रा से लेकर बैंक के अधिकारी व कर्मि शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने भी कइयों के खिलाफ पुछ्छा सुबूत जुटाए हैं।

काशी में बढ़ा गंगा का जलस्तर, गंगा आरती की निचली सीढ़ी तक पहुंचा पानी

वाराणसी , एजेंसी। गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर ने घाटों पर गतिविधियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को गंगा का जलस्तर करीब पांच सेंटीमीटर बढ़ने के बाद दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती की निचली सीढ़ी तक पानी पहुंच गया। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार शुक्रवार को गंगा का जलस्तर 60.55 मीटर दर्ज किया गया, जबकि बृहस्पतिवार को यह 60.50 मीटर था। यदि जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो अगले तीन-चार दिनों में गंगा आरती के मूल मंच तक भी पानी पहुंच सकता है। ऐसे में आरती की व्यवस्था ऊपरी हिस्से में स्थानांतरित करनी पड़ सकती है।

पिछले कुछ दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसका मुख्य कारण गंगा के ऊपरी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से छोड़ा जा रहा अतिरिक्त पानी है। जलस्तर बढ़ने का असर सबसे पहले घाटों की निचली सीढ़ियों पर दिखाई देता है, जहां स्नान, नौका संचालन और धार्मिक अनुष्ठान होते



हैं। दशाश्वमेध घाट पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक गंगा आरती देखने पहुंचते हैं। निचली सीढ़ियों तक पानी पहुंचने से श्रद्धालुओं के बैठने और आवाजाही की जगह कम हो गई है। जलस्तर बढ़ने का असर नौका संचालन पर भी पड़ने लगा है।

नाविकों को नाव बांधने के स्थान बार-बार बदलने पड़ रहे हैं और तेज धारा के कारण अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों ने घाटों पर गश्त बढ़ा दी है। सभी संवेदनशील घाटों पर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके।

छठवीं पास ने पढ़े-लिखे अमेरिकी नागरिकों को लगाया करोड़ों का चूना, लखनऊ में बैठकर विदेशियों को लूटते थे

लखनऊ , एजेंसी। क्राइम ब्रांच और साइबर सेल ने अमेरिकी नागरिकों से साइबर ठगी करने वाले एक और अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। सुशांत गोल्फ सिटी स्थित ओमेक्स आर-2 रेंजिडेंशियल अपार्टमेंट में संचालित इस कॉल सेंटर से सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हैरानी की बात यह है कि गिरोह के सरगना पुनीत कुमार वर्मा महज छठवीं और उसका साथी दीपेन चंद्रकांत पटेल आठवीं तक पढ़े हैं, लेकिन दोनों मिलकर विदेशी नागरिकों को झांसे में लेकर लाखों-करोड़ों रुपये की साइबर ठगी कर रहे थे।

कोई भी 12वीं से ज्यादा नहीं पढ़ा : पकड़े गए गिरोह में कोई भी 12वीं से ज्यादा नहीं पढ़ा है। पृष्ठताछ में पुनीत ने बताया कि गिरोह में कम पढ़े-लिखे लोगों को ही शामिल किया जाता था। इन्हें रहने-



खाने की व्यवस्था के साथ 35 हजार रुपये वेतन मिलता था। गिरोह में शामिल करने के लिए ऐसे लोगों का चयन होता था, जो बीपीओ के क्षेत्र में काम कर चुके हों और फर्स्टिदार अंग्रेजी बोलते हों। किसी को भी नियुक्ति पत्र या कोई दस्तावेज नहीं दिया जाता था। पूरा पैटर्न समिट बिल्डिंग में पकड़े गए फर्जी कॉल सेंटर की तरह था।

अरोपी ठगी को खम सोधे बैंक खातों में नहीं लेते थे। सारा लेनदेन पिफ्ट कार्ड, डिजिटल वाउचर और क्रिप्टोकॉर्सी के जरिये होता था। ऐसा करने का उद्देश्य

धन के वास्तविक स्रोत एवं अंतिम लाभार्थी के साथ जांच एजेंसियों के लिए वित्तीय ट्रेल को छिगना था।

हवाला से 70 फीसदी रकम भेजते थे अमेरिकी ठग : आरोपियों ने बताया कि अमेरिका में बैठे गिरोह के साथी 30 फीसद रकम अपने पास रखते थे। 70 प्रतिशत रकम हवाला के जरिये भारत भेजी जाती थी। हवाले की रकम ठिकाने लगाने और कर्मचारियों को बांटने का काम गुजरात में रहने वाला पुनीत का बड़ा भाई यश करता था। वहीं, अमेरिकी ठगों से संपर्क



से हो जाती है।

जान भी ले सकती हैं नकली दवाएं

डॉक्टरों का कहना है नकली दवाओं में उपचार के लिए आवश्यक सक्रिय तत्व नहीं होते या उसकी मात्रा मानक से बेहद कम या ज्यादा होती है। इससे बीमारी नियंत्रित होने के बजाय बढ़ सकती है। एंटीबायोटिक के मामलों में दवा के प्रतिरोध का खतरा बढ़ जाता है, जबकि गंभीर मरीजों में नकली दवा जान भी ले सकती है।

गहन जांच करने की जरूरत

लखनऊ केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रवक्ता मयंक रस्तोगी ने बताया कि नकली दवाओं के खिलाफ एफएसडीए की टीम अच्छा काम कर रही है। लखनऊ के मेडिसिन मार्केट में टीम ने 28 दुकानों का सर्वे किया था। जांच टीम में प्रदेश भर से बुलाए गए 17-18 ड्रा इंस्पेक्टर भी शामिल थे। किसी भी दुकान से नकली दवाएं बरामद नहीं हुईं। नकली दवाओं के मामले में काफी समय से आगरा का नाम आता रहा है। वहां पर गहन जांच करने की जरूरत है।

की इयूटी लगवाने की सिफारिश : गणना प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो इसको लेकर एसआईटी ने विस्तृत जांच में कई अहम सिफारिशें की हैं। अब गणना में जो बैंक कर्मी लगाए जाएंगे वह नियमित कर्मचारी होंगे। वहीं इनकी इयूटी बदलती रहेगी। हर पंद्रह दिनों में इन कर्मचारियों को बदला जाएगा। बैंक की तरफ से निगरानी के लिए एक अधिकारी भी तैनात होगा। एसआईटी ने इसके अलावा भी कई अहम सिफारिशें की हैं। जो जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद लागू की जाएंगी।

चढ़ावा चोरी की घटना में जो छह गणना कर्मी जेल गए हैं वह लिखापट्टी में हाउसकीपिंग के कार्य के लिए भर्ती किए गए थे गणना की इयूटी उनसे ट्रस्ट के पदाधिकारी करवा रहे थे। एसआईटी ने इसको सबसे बड़ी लापरवाही में से एक माना है। लिहाजा इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई बिंदुओं पर सिफारिश की है। पहला बिंदु ये है कि नियमित बैंक कर्मी ही इसमें तैनात किए जाएंगे। जो कर्मी होंगे उनमें ट्रस्ट के पदाधिकारियों का किसी तरह का हस्ताक्षेप नहीं होगा। दान पात्रों की चाबी ट्रस्ट के एक पदाधिकारी के पास होगी, जिसकी निगरानी में ही गणना होगी।

प्रदेश में आने वाले पांच दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, जारी हुआ विशेष अलर्ट

लखनऊ, एजेंसी। प्रदेश वासियों

को भीषण उमस और गर्मी से राहत मिलने वाली है। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग ने प्रदेश में मानसूनी सक्रियता और बादलों की आवाजाही को देखते हुए अगले पांच दिनों तक झमाझम बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसी के तहत राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अर्रेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बना एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र पिछले 48 घंटों में उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा है। शुक्रवार को यह पश्चिम बंगाल, उससे सटे झारखंड और उत्तरी ओडिशा के पास केंद्रित है। अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम के धीरे-धीरे कमजोर होकर उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने और मानसूनी ट्रफ के दक्षिण की ओर खिसकने की संभावना है। इसी मौसमी बदलाव के कारण प्रदेश में मानसून तेजी से सक्रिय हो रहा है।



18 से 23 जुलाई तक मानसूनी बारिश में बढ़ोतरी : प्रदेश में 18 से 23 जुलाई के बीच मानसूनी बारिश में व्यापक बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। भारी बारिश के चलते अगले तीन से चार दिनों में तापमान में चार से छह डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना है।मौसम विभाग ने भारी बारिश और अर्रेंज अलर्ट को देखते लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। विशेषकर आकाशीय बिजली चमकने के दौरान और जलभराव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है।

गन्ने का रस बेचने वाला दुकानदार बोला–लो कर लो सांसद के पीआरओ से बात

अलीगढ़ , एजेंसी। नगर निगम के प्रवर्तन दस्ते ने शुक्रवार को अस्थायी अतिक्रमण हटाने की अभियान चलाया। इस दौरान अभियान चला रहे अधिकारी एएमयू सर्किल के पास गन्ने का रस बेच रहे दिव्यांग दुकानदार आदिल की बात सुनकर भौंचक रह गए।

आदिल ने कार्रवाई रोकने के लिए अधिकारियों को फोन देकर सांसद के पीआरओ से बात कर लेने दबाव बनाया। फोन कॉल पर उनके पीआरओ थे या कोई और इसका तो पता नहीं चला लेकिन न उसकी अपील सुनी गई और सिफारिश। निगम के दस्ते ने उसका सामान जब्त कर लिया।

दोपहर करीब छह बजे नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान सारसौल से शुरू हुआ।

अभियान के दौरान सारसौल, नौरंगाबाद, मीनाक्षी पुल, एएमयू सर्किल, हैबिटेट सेंटर के पास सड़क किनारे किए गए अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान

कई दुकानदारों को पहले चेतावनी देकर स्वयं सामान हटाने का मौका दिया गया जबकि निर्देशों की अनदेखी करने वालों का सामान जब्त कर निगम की गाड़ियों में रखा गया। प्रवर्तन दल जैसे ही इन स्थानों पर पहुंचा तो फुटपाथ और सड़क पर सामान फैलाकर बैठे दुकानदारों में खलबली मच गई। कई दुकानदार जल्दबाजी में अपना सामान समेटने लगे। कोई फोन मिलाने लगा तो कोई पहचान का रौब दिखाने लगा तो कोई हाथ जोड़कर मोहलत मांगता नजर आया। हालांकि प्रवर्तन टीम का जवाब साफ था सिफारिश बाद में कर लीजिए, पहले सड़क खाली कराइें। कार्रवाई के दौरान सड़क पर रखा फर्नीचर, डेले, टेबल, स्टैंड, बोर्ड और अन्य सामान जब्त कर निगम की गाड़ियों में लादा गया।

कई दुकानदारों को मौके पर ही अंतिम चेतावनी देते हुए कहा गया कि यदि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो जुर्माने के साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कोरियर बन गया नकली दवाओं का सबसे बड़ा हथियार, लखनऊ में बढ़ता जानलेवा खतरा

लखनऊ, एजेंसी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग राजधानी में नकली दवाओं के नेटवर्क को तोड़ नहीं पा रहा। इसकी बड़ी वजह ये है कि राजधानी में नकली दवाओं की ज्यादातर आपूर्ति क्रूरियर के जरिये पहुंच रही है। जिले के अंदर और आसपास के जिलों में माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ही वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है।

अधिकारी भी मानते हैं कि दवा की दुकानों तक पहुंचने के बाद नकली-असली की पहचान करना काफी मुश्किल हो जाता है। नकली दवाओं को पकड़ने के लिए गोपनीय सूचनाओं पर आश्रित रहना पड़ता है। बृहस्पतिवार रात विभिन्न ब्रांड की नकली दवाओं की बरामदगी ने फिर से सवाल खड़े किए हैं कि आखिर इन दवाओं के निर्माण और सप्लाई का नेटवर्क कहाँ से संचालित हो रहा है।

पिछले तीन वर्ष में कई बार कार्रवाई के बाद भी नकली दवाओं के धंधे पर पूरी तरह से रोक नहीं लग सकी है। पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी मानते हैं कि जब तक नकली दवाओं के उत्पादन और

आपूर्ति पर नकेल नहीं कसेगी, तब तक इस धंधे को रोक पाना मुश्किल है।

दूसरे राज्यों से आ रही नकली दवाएं

एफएसडीए के सहायक मंडल आयुक्त ब्रजेश ने बताया कि पकड़ी गई नकली दवाओं की आपूर्ति दूसरे राज्यों से हो रही है। विभाग एक-एक कड़ी जोड़कर उन फर्मों पर नकेल कसने की तैयारी में है, जो नकली दवाओं के कारोबार में लिस हैं। ब्रजेश के अनुसार, नकली दवाओं की खेप क्रूरियर के जरिये लखनऊ पहुंच रही है जिसे आसपास के जिलों में खपाया जा रहा है।

ज्यादा प्रचलित दवाओं की करते हैं नकल

अब तक की जांच में सामने आया है कि नकली दवा के सौदागर उन दवाओं नकल ज्यादा करते हैं जो बेहद प्रचलित हैं। जिनका सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं जैसे दर्द, सूजन, सर्दी-जुकाम, बुखार के उपचार में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक, एंटीएलर्जिक और विटामिन सप्लीमेंट वाली नकली दवाएं भी खूब बनाई जाती हैं। बाजार में ऐसी दवाओं की मांग ज्यादा होती है तो इनकी बिज्री बेहद आसानी

संपादकीय रील्स नहीं, रियल स्किल्स बनाती हैं भविष्य

डिजिटल युग ने अवसरों की दुनिया को पहले से कहीं अधिक विस्तृत बना दिया है। आज एक साधारण स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नई ऊँचाइयाँ दी हैं। अनेक युवाओं ने अपनी मेहनत, रचनात्मकता और निरंतर प्रयास के बल पर इस माध्यम से पहचान, सम्मान और आर्थिक सफलता भी प्राप्त की है। यह परिवर्तन निश्चित रूप से तकनीकी क्रांति का सकारात्मक पक्ष है। किंतु इसी चमकदार दुनिया का एक दूसरा पक्ष भी है, जिसे अक्सर लाइक्स, व्यूज और वायरल वीडियो की चकाचौंध ढँक देती है। यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में युवा पारंपरिक शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और दीर्घकालिक करियर योजना की तुलना में सोशल मीडिया को ही सफलता का सबसे सरल और तेज रास्ता मानने लगे हैं। यह सोच जितनी आकर्षक दिखाई देती है, उतनी ही जोखिमपूर्ण भी है।

आज सोशल मीडिया पर हमें वही लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने लाखों-करोड़ों रुपये कमाए, महंगी गाड़ियाँ खरीदीं, आलीशान घर बनाए और कुछ वर्षों में लोकप्रियता की ऊँचाइयाँ छू लीं। लेकिन कैमरे के पीछे कुछ विशाल दुनिया ऐसी भी है जहाँ लाखों लोग प्रतिदिन वीडियो बनाते हैं, घंटों संपादन करते हैं, नए विचार खोजते हैं और फिर भी उन्हें न तो पर्याप्त दर्शक मिलते हैं और न ही आर्थिक स्थिरता। सफलता की कहानियाँ वायरल होती हैं, संघर्ष की कहानियाँ ऑँकड़ों में दब जाती हैं। यही चयनात्मक दृश्य युवाओं में घम पैदा करता है कि यदि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया से जीवन बदल लिया है तो हर व्यक्ति ऐसा कर सकता है।

वास्तविकता यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सफलता अत्यंत असमान रूप से वितरित होती है। कुछ प्रतिशत शीर्ष क्रिएटर्स अधिकांश दर्शकों, विज्ञापनों और आय पर अधिकार कर लेते हैं, जबकि शेष लाखों लोग सीमित अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। यह स्थिति केवल भारत में नहीं बल्कि विश्वभर में देखी जाती है। अधिकांश कंटेंट क्रिएटर्स अपनी सामग्री से स्थायी और सम्मानजनक आय अर्जित नहीं कर पाते। इसलिए, सोशल मीडिया को निश्चित करियर मान लेना आर्थिक दृष्टि से एक जोखिमपूर्ण निर्णय हो सकता है।

इसका अर्थ यह नहीं कि सोशल मीडिया बुरा है या उस पर करियर बनाना गलत है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब युवा बिना किसी वैकल्पिक कौशल, शिक्षा या पेशेवर योग्यता के केवल वायरल होने की उम्मीद पर अपना भविष्य दौंव पर लगा देते हैं। इंटरनेट पर प्रसिद्धि प्राप्त करना और लंबे समय तक आर्थिक रूप से सफल बने रहना दो अलग-अलग बातें हैं। आज जो वीडियो करोड़ों लोग देख रहे हैं, संभव है कुछ महीनों बाद वही दृश्य किसी नए चेहरे की ओर आकर्षित हो जाएँ।

डिजिटल दुनिया में लोकप्रियता का चक्र अत्यंत तेज गति से बदलता है। सफलता की सबसे बड़ी चुनौती इसकी अनिश्चितता है। यहाँ आपका भविष्य केवल आपके प्रतिभा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम, विज्ञापन नीतियों, कॉपीराइट नियमों, तकनीकी बदलावों और दर्शकों की बदलती रुसंद पर भी निर्भर करता है। एक छोटे से एल्गोरिदमिक परिवर्तन से लाखों फॉलोअर्स वाले अकाउंट की पहुँच अचानक घट सकती है। किसी नीति परिवर्तन से आप का प्रमुख स्रोत समाप्त हो सकता है। किसी तकनीकी त्रुटि या अकाउंट निलंबन से वर्षों की मेहनत प्रभावित हो सकती है। ऐसी अनिश्चितता किसी भी व्यक्ति के लिए दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा का आधार नहीं बन सकती। इसके विपरीत वास्तविक कौशल की दुनिया कहीं अधिक स्थिर है। एक चिकित्सक की चिकित्सा-योग्यता, एक शिक्षक का ज्ञान, एक इंजीनियर की तकनीकी क्षमता, एक वकील का विधिक अनुभव, एक किसान की कृषि विशेषज्ञता, एक प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन या मशीन ऑपरेटर का व्यावसायिक कौशल किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं होता। समय के साथ तकनीक बदल सकती है, लेकिन वास्तविक कौशल की आवश्यकता समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि समाज की मूल संरचना शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, उद्योग और तकनीकी दक्षता पर आधारित रहती है, न कि वैकल्पिक डिजिटल लोकप्रियता पर।

आज अनेक युवा पढ़ाई से अधिक समय रील बनाने, ट्रेंड खोजने और फॉलीअर्स बढ़ाने में लगाने लगे हैं। कई बार विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी यह देखा जाता है कि विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी से अधिक अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल की चिंता करते हैं। यह प्रवृत्ति चिंताजनक है, क्योंकि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अर्जित ज्ञान और कौशल ही भविष्य की सबसे बड़ी पूँजी होते हैं। यदि यह समय केवल तात्कालिक लोकप्रियता के पीछे व्यतीत हो जाए तो आगे चलकर प्रतिस्पर्धी रोजगार बाजार में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस विषय का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। सोशल मीडिया लगातार तुलना की संस्कृति को बढ़ावा देता है। युवा दूसरों की सफलता देखते हैं, लेकिन उनके संघर्ष, असफलता और वर्षों की मेहनत नहीं देख पाते। परिणामस्वरूप उन्हें लगता है कि सफलता बहुत आसान है और यदि वे कुछ महत्त्व नहीं हासिल नहीं हुए तो वे असफल हैं। यह सोच आत्मविश्वास को कमजोर करती है और मानसिक तनाव बढ़ाती है। वास्तविक जीवन में सफलता अक्सर वर्षों की तैयारी, अनुशासन, धैर्य और निरंतर अभ्यास का परिणाम होती है, जबकि सोशल मीडिया तात्काल परिणामों की अपेक्षा पैदा करता है।

यह भी सत्य है कि कंटेंट निर्माण स्वयं एक महत्वपूर्ण कौशल है। वीडियो संपादन, कहानी कहने की कला, मेकरा संचालन, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग और संचार क्षमता आज के समय में उपयोगी दक्षताएँ हैं। यदि कोई युवा इन कौशलों को व्यवस्थित रूप से सीखकर उन्हें किसी पेशे, व्यवसाय या विशेषज्ञता के साथ जोड़ता है, तो सोशल मीडिया उसके लिए अत्यंत प्रभावी मंच बन सकता है। उदाहरण के लिए एक चिकित्सक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा कर सकता है, एक शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा दे सकता है, एक किसान आधुनिक कृषि तकनीक समझा सकता है, एक इंजीनियर तकनीकी समाधान प्रस्तुत कर सकता है।

क्या फिर से लौट रहा कोरोना वायरस?

महेन्द्र तिवारी

कोरोना महामारी ने दुनिया को जो अनुभव दिया, उसने स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन तक सब कुछ बदल दिया। वर्षों तक चले लॉकडाउन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और टीकाकरण अभियानों के बाद जब जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, तब अधिकांश लोगों ने यह मान लिया कि कोरोना अब इतिहास बन चुका है। लेकिन हाल के दिनों में देश के कुछ राज्यों से कोविड 19 के नए मामले सामने आने और आंध्र प्रदेश में संक्रमण से दो लोगों की मौत की खबर ने एक बार फिर लोगों के मन में पुराने सवाल जाग दिए हैं। क्या कोरोना वायरस फिर लौट रहा है? क्या फिर मास्क पहनना अनिवार्य होगा? क्या सोशल डिस्टेंसिंग की वापसी होगी? या यह केवल सीमित स्तर पर संक्रमण का सामान्य उतार चढ़ाव है?

हाल की घटनाओं पर नजर डालें तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में कोविड 19 के आठ सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है और दो संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य सरकार ने निगरानी, सैंपलिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग और अस्पतालों की तैयारियों को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने अस्पतालों में आवश्यक दवाओं, जांच किट और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा है। यह कदम इस बात का संकेत है कि स्वास्थ्य तंत्र किसी भी संभावित स्थिति के लिए पहले से तैयार रहना चाहता है।

उत्तर प्रदेश में वाराणसी के अशापुर क्षेत्र के 27 वर्षीय युवक की कोविड जांच पॉजिटिव आने के बाद उसे बीएचप्यू अस्पताल में भर्ती कराया



गया। युवक को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत थी। इसी तरह महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई में भी कुछ नए मामलों की पुष्टि हुई है। इन घटनाओं के बाद संबंधित राज्यों के स्वास्थ्य विभागों ने सतर्कता बढ़ा दी है। हालांकि मामलों की संख्या अभी बहुत अधिक नहीं है, लेकिन अलग अलग राज्यों में संक्रमण का दिखाई देना इस बात की याद दिलाता है कि वायरस पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इन खबरों के बीच प्रसिद्ध गायक और बिग बॉस 14 के पूर्व प्रतिभागी जान कुमार सानू के कोरोना संक्रमित होने की खबर भी चर्चा का विषय बनी। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के संक्रमित होने पर आम लोगों का ध्यान स्वाभाविक रूप से इस ओर जाता है, लेकिन किसी एक या कुछ मामलों को व्यापक महामारी का संकेत मान लेना उचित नहीं होगा। महामारी विज्ञान में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संक्रमण की दर, अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या, गंभीर मरीजों का अनुपात और सामुदायिक प्रसार जैसे कई संकेतकों का अध्ययन किया जाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड

19 का वायरस अब पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यह अन्य श्वसन संक्रमणों की तरह समय समय पर नए स्वरूपों के साथ सामने आ सकता है। अधिकांश देशों में अब कोविड की निगरानी सामान्य सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर नया मामला नई महामारी की शुरूआत है, बल्कि यह कि स्वास्थ्य तंत्र लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या फिर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की वापसी होगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसका उत्तर फिलहाल नहीं है। केंद्र स्तर पर ऐसी कोई नई राष्ट्रीय अनिवार्य गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसमें सभी नागरिकों के लिए मास्क पहनना या सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य किया गया हो। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह सलाह अवश्य दे रहे हैं कि भीड़भाड़ वाले स्थानों, अस्पतालों और बंद कमरों में मास्क पहनना अभी एक अच्छा प्रवृत्तिायी उपाय है। जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, बुजुर्ग हैं या पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें अतिरिक्त

कम और पाने के लिए बहुत कुछ

है। यदि कांग्रेस अकेले लड़ने का निर्णय लेती है, तो वह राज्य में अपनी विचारधारा को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर सकती है और भविष्य में एक मजबूत विकल्प के रूप में खुद को तैयार कर सकती है। हालांकि, यह राह इतनी सरल नहीं है। एकला चलो की राजनीति करने का अर्थ है मुस्लिम और दलित वोटों के उस समीकरण को चुनौती देना, जिसे फिलहाल सपा और बसपा अपनी जागीर समझते हैं। यह प्रयोग सफल होगा या विफल, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन यह निश्चित है कि इससे विपक्षी एकता का ढांचा बुरी तरह चरमरा जाएगा। कांग्रेस शायद यह मानकर चल रही है कि यदि वह गठबंधन में रहकर अपनी पहचान खो रही है, तो उससे बेहतर है कि अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ इस लड़ाई को लड़ा जाए, भले ही इसका परिणाम तत्काल न मिले। दबाव की राजनीति के चश्मे से देखें, तो कांग्रेस का यह रख सपा को आईना दिखाने जैसा है। सपा ने लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस को गठबंधन में तो शामिल किया, लेकिन सीटों के बंटवारे और चुनावी प्रबंधन में उसने कांग्रेस की भूमिका को काफी सीमित रखा। कांग्रेस को यह अहसास हो चुका है कि यदि उसने अभी अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया और अपनी ताकत का समर्थन सपा को नहीं कराया, तो आने वाले विधानसभा चुनावों में

भी उसे जूनियर पार्टनर बनकर ही संतोष करना पड़ेगा। इमरान मसूद का हमला इसी अस्तोष की अभिव्यक्ति है। यह एक संदेश है कि यदि कांग्रेस की राजनीतिक गरिमा और चुनावी महत्व को नजरअंदाज किया गया, तो गठबंधन के भीतर भी संघर्ष अनिवार्य है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश यादव इस दबाव को झेलते हुए कांग्रेस के साथ सामंजस्य बिठा पाते हैं, या फिर यह दरार और बढ़ती जाती है।गौरतलब हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अल्पसंख्यकों का वोट बैंक हमेशा से निर्णायक रहा है। कांग्रेस और सपा दोनों ही इस वोट बैंक को अपना आधार मानती हैं। कांग्रेस का वर्तमान रख इस वोट बैंक में अपने पुराने वर्चस्व को पुनः प्राप्त करने की कोशिश का एक हिस्सा प्रतीत होता है। यदि कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं को यह समझाने में सफल रहती है कि सपा केवल सत्ता के लिए उनका उपयोग कर रही है और कांग्रेस उनके दीर्घकालिक हितों के लिए बेहतर है, तो यह समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता फिलहाल सपा के साथ अधिक सहज है, क्योंकि उससे भाजपा को हराने की क्षमता उसमें ही दिखती है। ऐसे में कांग्रेस का एकला चलो वाला दांव कहीं उल्टा न पड़ जाए, यह उर भी कांग्रेस के रणनीतिकारों को सता रहा होगा।

यूपी में कांग्रेस क्यों दिखा रही है अखिलेश को आंखें

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश की राजनीति अपनी उलटिलताओं और अप्रत्याशित करवोटों के लिए जानी जाती है, और वर्तमान में राज्य में जो सियासी घटनाक्रम घटित हो रहा है, वह उसी परंपरा का एक नया अध्याय है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस द्वारा अपने ही गठबंधन सहयोगी, समाजवादी पार्टी (सपा) के खिलाफ खोला गया मोर्चा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। सतह पर यह एक सामान्य राजनीतिक बयानबाजी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे के निहितार्थ काफी गहरे और दूरगामी हैं। कांग्रेस का यह कदम स्पष्ट रूप से दबाव की राजनीति (प्रेसर पॉलिटिक्स) का एक हिस्सा माना जा रहा है, जहाँ पार्टी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए जोखिम लेने से भी पीछे नहीं हट रही है। लंबे समय से उत्तर प्रदेश में हाथियार पर लीनी कांग्रेस अब अपनी रणनीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करने के संकेत दे रही है। यदि इस स्थिति का बारीकी से विश्लेषण किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस अब हम त् दो डूबेंगे ही, तुमको भी ले डूबेंगे की तर्ज पर आगे बढ़ रही है, जिसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता पर पड़ना तय है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद द्वारा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव



जन सुराज ने खुद को साफ-सुथरी राजनीति का मसौदा घोषित किया था। परंतु जब धरातल पर टिकट वितरण की बारी आई, तो पार्टी की वही आरोप लगे जो वह पारंपरिक भाटियों—राजद, जन्सू और पाटिया—पर लगाती आई थी। कई निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर ऐसे रसखुदार उम्मीदवारों को तर्जही दी

गई, जिनकी छवि स्वच्छ नहीं थी।पार्टी के भीतर विद्रोह की दूसरी सबसे बड़ी वजह यह रही कि आंतरिक रूप से टिकटों की खरीद-बिक्री और पैसे के लेन-देन के आरोप लगने लगे। समर्पित कार्यकर्ताओं ने महसूस किया कि जिस नई राजनीति के लिए उन्होंने महीनों पदयात्रा की, पसीना बहाया, उसे अंततः चुनावी गणित की वेदी

क्या भारत विरोध ने पाकिस्तान को आर्थिक संकट में धकेला?

महेन्द्र तिवारी

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह का हालिया बयान दक्षिण एशिया की राजनीति में व्यापक चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अधिक विरोधी की नीति न अपनाता और भारत के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ता, तो आज पाकिस्तान को कर्ज के लिए दर दर नहीं षटकना पड़ता। उन्होंने यह भी कहा कि भारत से मैत्रीपूर्ण संबंध होते तो पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता का वातावरण बनता। किसी विराट पाकिस्तानी नेता की ओर से इस प्रकार का आत्मविश्लेषण असामान्य माना जा रहा है। क्योंकि दशकों से पाकिस्तान की राजनीतिक और सामरिक सोच का बड़ा हिस्सा भारत विरोध पर आधारित रहा है। राणा सनाउल्लाह ने अपने बयान में वर्ष 2015 का उल्लेख किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लाहौर पहुंचे थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। उस समय उस दोनों देशों के संबंधों में नई शुरुआत की संभावना के रूप में देखा गया था। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद पठानकोट आतंकी हमला हुआ और उसके बाद दोनों देशों के संबंध फिर से तनावपूर्ण हो गए। राणा सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान उस अवसर का

लाभ उठाने में विफल रहा और इसके लिए स्वयं पाकिस्तान की राजनीतिक सोच तथा भारत विरोधी दृष्टिकोण जिम्मेदार रहा। भारत और पाकिस्तान के संबंधों का इतिहास विभाजन के समय से ही जटिल रहा है। दोनों देशों ने अनेक युद्ध देखे, सीमा पर लगातार तनाव बना रहा और आतंकवाद के मुद्दे ने विश्वास की कमी को और गहरा किया। कश्मीर विवाद ने भी संबंधों को सामान्य होने नहीं दिया। समय समय पर शांति वार्ताएँ हुईं, व्यापार बढ़ाने के प्रयास किए गए और सांस्कृतिक आदान प्रदान की पहल भी हुई, लेकिन हर बार कोई न कोई घटना संबंधों को पीछे धकेल देती रही। इस पृष्ठभूमि में किसी पाकिस्तानी वरिष्ठ नेता द्वारा यह स्वीकार करना कि अवसर गंवाया गया, अपने आप में महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कई वर्षों से गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, बढ़ता राजकोषीय घाटा, महंगाई, ऊर्जा संकट और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से बार बार सहायता लेने की मजबूरी ने उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है। अनेक विशेषज्ञ लंबे समय से यह तर्क देते रहे हैं कि यदि दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग बढ़े और भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापार सामान्य हो, तो दोनों देशों को लाभ मिल सकता है।

पर बलि चढ़ा दिया गया। इसी अंतर्विरोध ने बगावत की आग में घी का काम किया और पार्टी के कई संस्थापक सदस्य व पूर्व प्रत्याशी पाला बदलने को मजबूर हो गए।

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान जन सुराज को सबसे तीखा झटका तब लगा जब 2025 के चुनाव में जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ चुके तीन बड़े चेहरे पार्टी छोड़ गए: पहले पी. डॉ. के.सी. सिन्हा जिनकी जो कुम्हार सीट से पूर्व प्रत्याशी, जिनकी शैक्षणिक और सामाजिक साख मजबूत थी।दूसरे रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह जो दीपा विधानसभा से जन सुराज के मुख्य चेहरा रहे। तीसरे संदीप कुमार सिंह उर्फ गोपाल सिंह जो मनेर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की जमीन तैयार करने वाले अहम नेता।इन नेताओं का एक साथ भाजपा के प्रदेश

कार्यालय में जाकर सदस्यता ग्रहण करना केवल सीटों का नुकसान नहीं है; यह जन सुराज के उस नैतिक आधामंडल को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है, जिसमें वे खुद को भाजपा और राजद दोनों के खिलाफ एकमात्र शुद्ध विकल्प बताते थे। यह बगावत साबित करती है कि पार्टी के भीतर का अनुशासन और निष्ठा पूरी तरह से तार-तार हो चुकी है।

ज्ञात हो कि प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए एक शॉर्टकट अपनाया था। उन्होंने विभिन्न दलों के असंतुष्ट पूर्व विधायकों, सेवानिवृत्त नौकरशाहों और बड़े व्यापारियों को पार्टी की कोर कमेटियों में शामिल किया। राजनीति का यह शाश्वत नियम है कि जो नेता केवल अवसरवादिता और सत्ता की संभावना देखकर किसी नए दल में आते हैं, वे संकट के पहले संकेत पर ही सबसे पहले

जहाज छोड़ देते हैं। 2025 की ऐतिहासिक हार के बाद जब जन सुराज का राजनीतिक ग्राफ नीचे गिरा, तो इन आयातित नेताओं ने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तुरंत सुरक्षित ठिकानों (जैसे भाजपा) की तलाश शुरू कर दी। जन सुराज अपनी खुद की कैंडा-आधारित लीडरशिप तैयार करने में पूरी तरह नाकाम रही। इस चौराहा संकट और बगावत के बीच, प्रशांत किशोर हार मानने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। वे इस संकट को ही एक नए सियासी अवसर में बदलने की आक्रामक तैयारी कर रहे हैं। पार्टी ने अपनी चुनावी और सांगठनिक रणनीति को पूरी तरह री-डिजाइन करना शुरू कर दिया है। जन सुराज की सबसे पहली और सबसे बड़ी भागी रणनीति का उदाहरण बांकीपुर उपचुनाव में ही दिख गया है।

अशोक भाटिया प्रशांत किशोर के लिए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का मैदान सचरूप सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने जैसा साबित हो रहा है। 30 जुलाई 2026 को होने जा रहे इस उपचुनाव से उन्होंने अपने जीवन का पहला प्रत्यक्ष चुनाव लड़ने का साहसिक फैसला लिया, लेकिन चुनावी रण में उतरते ही उनकी पार्टी जन सुराज गहरे सांगठनिक संकट और बगावत की शिकार हो गई।जैसे ही प्रशांत किशोर ने पर्दे के पीछे की राजनीति छोड़ खुद चुनावी मैदान में कदम रखा, उनके अभियान को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे हैं: विहार की सियासत में वैकल्पिक विमर्श का झंडा बुलंद करने वाली प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ही इस समय अपने अस्तित्व के सबसे बड़े सांगठनिक संकट और आंतरिक बगावत से जूझ रही है। वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 236 सीटों पर करारी हार और जमानत जब्त होने के बाद सुरज हुई अंतर्कोलह अब एक खुली बगावत का रूप ले चुकी है। चुनावी रणनीतियों को धरातलीय राजनीति में बदलने की सीमाओं और सांगठनिक अपरिपक्वता का यह ज्वलंत उदाहरण है। गौरतलब है कि कुछ समय पूर्व जब प्रशांत किशोर ने बिहार की सड़कों पर 3,500 किलोमीटर से अधिक की लंबी पदयात्रा शुरू की थी, तब उन्होंने एक ऐसे वैकल्पिक राजनीतिक मॉडल का खाका खींचा था जो जाति, धर्म और धनबल की पारंपरिक राजनीति से ऊपर उठकर एक नए सिद्धांत को टोम लेती रही है। जब 2025 के चुनाव नतीजों के बाद प्रशांत किशोर ने पूरी राज्य कार्यकारिणी और सभी सांगठनिक इकायों को अचानक भंग कर दिया, तो इसने पार्टी के भीतर एक अविश्वास और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया। नेताओं को लगा कि उनकी अपनी जमीन और पहचान को दरकिनार कर दिया गया है। जब संगठन को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने के बजाय एक प्रबंधकीय संस्थान की तरह चलाया जाने लगा, तो नेताओं का मोहभंग होना स्वाभाविक था।

तिरुपति में दानवीरों का सैलाब : नई नीति से पहले 97 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड संग्रह

तिरुपति (एजेंसी) । तिरुपति बालाजी मंदिर में दानदाताओं की अप्रत्याशित भीड़ देखने को मिली, जिसके चलते देवस्थानम बोर्ड ने मात्र 24 घंटों के भीतर रिकॉर्ड 96.98 करोड़ रुपये का दान जमा किया। यह अप्रत्याशित बढ़ोतरी 15 जुलाई की आधी रात से लागू होने वाली नई दानवर्ती नीति से ठीक पहले दानदाताओं में मची होड़ का परिणाम थी। इस नई नीति से दानदाताओं को अब तक मिलने वाले आजीवन लाभों पर विराम लग गया है, और सुविधाओं व विशेषाधिकारों में भी बड़े बदलाव किए हैं। हालांकि, जिन्होंने 15 जुलाई से पहले दान दिया है, उन्हें अपने आजीवन लाभ मिलता रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को 2,460 दानदाताओं ने योगदान दिया। इसमें से 1,212 भक्तों ने 1 से 10 लाख रुपये के बीच, जबकि 1,246 ने 10 से 25 लाख रुपये के बीच दान दिया। दो भक्तों ने 1 करोड़ रुपये से अधिक का महादान किया। दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार तिरुपति बालाजी की कुल संघति लगभग 3.38 लाख करोड़ रुपये है, जो छोटें देशों की जीडीपी से भी अधिक है। मंदिर की हुंडी में औसतन रोजाना 4.75 करोड़ रुपये का दान आता है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) बोर्ड ने दानदाताओं की बढ़ती संख्या को देखकर विशेष सुविधा नीति में बदलाव करना आवश्यक बताया। टीटीडी के चेयरमैन बी.आर. नायडू ने कहा कि पिछले चार महीनों में 10 लाख रुपये से अधिक दान करने वालों की संख्या में करीब 3,000 की बढ़ोतरी हुई है। नई नीति का उद्देश्य दान प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता लाना है, साथ ही आम तीर्थयात्रियों के लिए दर्शन के अवसरों को भी बेहतर बनाना है।

मुर्शिदाबाद में ट्रेन ने स्कूल वैन को मारी टक्कर, तीन की मौत



मुर्शिदाबाद (एजेंसी) । पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में ट्रेन की चोट में आने से स्कूल बैन में सवार कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो नाबालिग बच्चे बताए जा रहे हैं। हादसे में घायल अन्य लोगों को उपचार के लिए मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, हादसा शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे कर्मापुरगं रेलवे स्टेशन के पास रियल रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर हुआ। बताया जा रहा है कि स्कूल वैन रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही थी, तभी ट्रेन रफ्तार ट्रेन ने वैन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर टीख-पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही आरपास के सैकड़ों लोग रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। स्थानीय लोगों ने वैन में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे की 10 सक्स्टीय टीम मौके पर पहुंच गई है। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक रेलवे या स्थानीय प्रशासन की ओर से हादसे के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। अधिकारियों द्वारा घटना के कारणों और मृतकों तथा घायलों की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। हादसे के बाद क्षेत्र में तनाव और शोक का माहौल है।

रुद्रप्रयाग में खाई में डंपर गिरने से दो की मौत

रुद्रप्रयाग (एजेंसी) । उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। देर रात फाटा और बड़प्पू के बीच एक डंपर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उसमें सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हाल ही में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भी एक युवक खाई में गिर गया था, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकालकर मिसाल पेश की है। गुरुवार देर रात तरसाली के पास हुए इस डंपर हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं। रातभर चले संयुक्त रेस्क्यू अभियान के दौरान 45 वर्षीय संजय राणा और मोहन नामक दो व्यक्तियों के शव खाई से बरामद कर सड़क पर पहुंचाए गए। पुलिस ने दोनों शवों का पोचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। इससे पहले गौरीकुंड से करीब दो किलोमीटर ऊपर छोड़ी क्षेत्र में 25 वर्षीय मोहित रावत नाम का युवक खाई में गिर गया था। डायल-112 पर सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ और अन्य बचाव दलों ने अंधेरे और दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद कड़ी मशकत कर मौतों को सुरक्षित निकाल लिया। उसे उठे चोट आई हैं, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक के खाई में गिरने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

बरेली में गोकशी के आरोप में दो गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी और एक सिपाही घायल

बरेली(एजेंसी) । उत्तर प्रदेश के बरेली में गोकशी के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक को पुलिस मुठभेड़ के बाद दबोचा गया। इस कार्रवाई में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 16 जुलाई को इज्जतनगर पुलिस को ग्राम महलन में गोकशी की सूचना मिली थी। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने छपा मारकर मोहम्मद खान को मौके से गिरफ्तार किया। उसके पास से लगभग 40 किलो गोमांस, झलवाट्टीन वजन करने वाली मशीन और गोकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए। पुछताछ में मोहम्मद खान ने स्वीकार किया कि उसने अपने जीजा अकीलुद्दीन उर्फ 'बूढ़े, बहन हसीना और आलम उर्फ अकबर के साथ मिलकर गोकशी की थी। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस को सूचना मिली कि अकीलुद्दीन इलाके में छिपा है। उसे पकड़ने के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में अकीलुद्दीन के पैर से गोली लगी और उसे बाद में पुलिस ने दबोच लिया। उसके पास से एक तमचा, कारतूस और गोमांस के कुछ टुकड़े भी बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गतिरत कर वीरश दी जा रही है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

मानसून सत्र से पहले कांग्रेस का बड़ा प्लान, मोदी सरकार की घेराबंदी की तैयारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के आगामी मानसून सत्र से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरने की अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। गुरुवार को कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जिन्हें सदन में प्रमुखता से उठाया जाएगा।

इस बैठक में फैसला किया गया कि कांग्रेस शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं, लगातार हो रहे पेपर लीक, राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी जैसे भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार से कड़ा जवाब मांगेगी। इसके अतिरिक्त, एथनल मिश्रण नीति, कमरतोड़ महंगाई, विदेश नीति की कथित विफलताएं, संस्थानों पर बढ़ते कब्जे और राजनीतिक दलों को तोड़ने की प्रवृत्ति को भी उठाया जाएगा। पार्टी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा क्वां (ओबीसी) और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हो रहे लगातार हमलों तथा बेलागम वनों की कटाई से जुड़े पर्यावरण संबंधी चिंताओं को भी सदन में उठाने का संकल्प लिया है।

सुप्रीम कोर्ट की दो टूक कहा- कानून के दायरे में ही चलेगा बुलडोजर

नई दिल्ली(एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बुलडोजर कार्रवाई पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि कानून के लिए बुलडोजर चल सकता है, लेकिन इसका उपयोग चुनिंदा लोगों को निशाना बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने साफ़किया कि उसके पहले के फैसले में सभी बुलडोजर कार्रवाइयों पर रोक नहीं लगाई गई थी, बल्कि यह सुनिश्चित किया गया था कि तोड़-फोड़ की कार्रवाई कानून और संविधान के दायरे में ही हो। यह टिप्पणी मनमाने ढंग से बुलडोजर एक्शन के आरोपों वाली अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जय्यमल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि हर बुलडोजर एक्शन की वैधता की जांच उसके अपने तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए और ऐसे मामलों की जांच के लिए हाईकोर्ट ही सही जगह है।

बेंच ने अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि उठाए गए मुद्दों में तथ्यों से जुड़े विवादि सवाल शामिल हैं, जिनकी विस्तार से जांच की आवश्यकता है। जस्टिस जय्यमल्य की बागची ने टिप्पणी की कि अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल सही हो सकता है, विशेषकर जब अधिकारियों और अवैध कब्जा करने वालों की मिलीभगत से कानून का शासन कमजोर हो रहा हो। हालांकि, उन्होंने भेदभावपूर्ण तरीके से इसके इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी और कहा

कि कानून लागू करने के नाम पर लोगों की छवि खराब नहीं की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जोर दिया कि किसी भी विध्वंस यानी तोड़-फेंड के मामले में मुख्य मुद्दा यह होता है कि क्या वह ढांचा कानूनी रूप से अधिकृत था और क्या अधिकारियों ने कार्रवाई करने से पहले तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किया था। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 (संभवतः 2023 या पहले का संदर्भ) के फैसले में तय सुस्था उपायों का उल्लंघन किया है। हालांकि, बेंच ने कहा कि उन आरोपों के लिए तथ्यों की जांच जरूरी है, इसलिए यह जांचने के लिए कि क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था, हाई कोर्ट ही सही मंच है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी लंबित याचिकाओं को संबंधित हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया, और यह स्पष्ट किया कि उसके पूर्व के फैसले को उसमें बनाए न कि अपवादा के साथ पढ़ा जाना चाहिए, न कि किसी अलग कानूनी प्रावधान के तौर पर। बेंच ने यह भी कहा कि बुलडोजर एक्शन के अलग-अलग मामलों में तथ्यों से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए अवमानना की कार्यवाही सही तरीका नहीं है। वरिष्ठ अधिकारकों ने सुनवाई के दौरान विभिन्न मामलों का हवाला दिया, जिसमें सोमाथली सुनिश्चित करना भी शामिल है। उन्होंने लोगों से स्थानीय नेताओं द्वारा बुलडोजर कार्रवाई का आह्वान करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शामिल थी।

अखिलेश की रथ यात्रा: 36 साल बाद धार्मिक स्थलों से भाजपा को घेरने की तैयारी?

यात्रा की शुरुआत किसी प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल करने की चर्चा

लखनऊ (एजेंसी)। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इन्हीं चुनाव तैयारी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव एक बड़ी राजनीतिक कलाकदम की तैयारी में हैं। सूत्रों के अनुसार, अखिलेश सितंबर 2026 में समाजवादी पीछीए रथ यात्रा शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। यह यात्रा 25 सितंबर, 1990 को राम मंदिर आंदोलन के लिए निकाली गई चर्चित रथ यात्रा के 36 साल पुराने इतिहास को दोहराने जैसा होगा। माना जा रहा है कि अखिलेश की यह रथ यात्रा सितंबर के पहले समाह में शुरू हो सकती है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, यात्रा की शुरुआत किसी प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल से किए जाने पर मंजूर चल रहा है, जिसमें अयोध्या, मथुरा या काशी जैसे स्थानों पर विचार हो रहा है। सपा की रणनीति भाजपा को राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर राजनीतिक रूप से घेरने की हो सकती है, हालांकि पार्टी नेतृत्व अभी अंतिम स्थान और तरीका को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यह यात्रा समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडब्लू) समीकरण को साधने पर



केंद्रित होगी।

समाजवादी पार्टी के इन दावों के बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा से संबंधित हालिया बयान चर्चा में है। कुशीनगर में जनसभा के दौरान, मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला कर कहा था कि वो लोग युवाओं का रोजगार छिनते थे, वे अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में

हालांकि, संक्रामक रोग विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल देश में कोरोना की कोई नई लहर नहीं है और न ही कोई देशस्तक वैरिएंट सामने आया है। आंध्र प्रदेश के मामले स्थानीय क्लस्टर प्रतीत होते हैं, न कि देशव्यापी फैलाव। जानकार बताते हैं कि एक बड़ी आबादी में अब हाइड्रिड इम्यूनिटी मौजूद है, जो गंभीर बीमारी से

कैसे सोच सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसों को हजम कर जाती थी और मंदिरों पर कब्जा करवाती थी, जबकि भाजपा सरकार उन्हीं मंदिरों का पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण कर रही है। योगी ने कहा कि मंदिरों का पैसा कब्रिस्तान की चारदीवारी पर खर्च करने वाले लोगों को विकास पर बात करना शोभा नहीं देता।

कोरोना की वापसी की आशंका: 4 मौतें और 12 नए केस से हड़कंप

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में कोविड-19 के कुछ नए मामलों और मौतों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है, जिससे बीमारी की वापसी का खतरा मंडराने लगा है। आंध्र प्रदेश में 26 जून से 16 जुलाई के बीच 12 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए, जिसमें से चार मरीजों की पहले से मौजूद गंभीर बीमारियों और कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के कारण मौत हो गई। इन मौतों का अनुपात लगभग 30 प्रतिशत रहा, जिसने लोगों को विशेष रूप से भयमंद कर दिया है। मरने वाले मरीजों को हाइपरटेंशन, डायबटीज और किडनी संबंधी गंभीर समस्याएं थीं। शेष संक्रमितों में से तीन होम

बचाती है। इम्प्लूएजा और कोविड के लक्षण मिलते-जुलते हैं, इसलिए जांच महत्वपूर्ण है। उन्होंने विशेष रूप से बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पुरानी बीमारियों से ग्रसित लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। यदि बुखार 3-5 दिन से अधिक रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में दर्द हो या भ्रम बढ़े, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मास्क के उपयोग पर विशेषज्ञों का कहना है कि हर किसी को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि किसी को बुखार, खांसी, गले में खराश या नाक बह रही है, तो दूसरों में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए मास्क जरूर पहनें। अस्पताल जाते समय या

भीड़भाड़ वाली बसों, ट्रेनों और फ्लाइट्स में भी मास्क का उपयोग करना उचित है। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पुरानी बीमारियों वाले लोगों को भीड़ वाली बंद जगहों पर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ जरूरी सावधानियों में भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना, बाहर से आने के बाद हाथों को साबुन और पानी से धोना, खांसी या जुकाम होने पर मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना शामिल है। यदि बढ़ते बीमार हो, तो उन्हें स्कूल या खेलने न भेजें और घर पर उचित वैटिलेशन की व्यवस्था बनाए रखें। घरबाने के बजाय सतर्कता और सावधानी ही इस स्थिति से निपटने का सर्वोत्तम उपाय है।

भक्त चरण दास ने इस तरह की घटनाओं के बार-बार होने को गंभीर चिंता का विषय बताया और इसकी गहन समीक्षा की मांग की। उन्होंने घटना को अक्षय्य बताते

पंजाब कांग्रेस में घमासान : राहुल से नहीं मिल पाए चन्नी, बुलाई समर्थकों की मीटिंग

चंडीगढ़ (एजेंसी) । अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह लगातार खुलकर सामने आ रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िग के बीच गुटबाजी लंबे समय से चल रही है। हाल ही में, चन्नी और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि ऑल इज वेल और वे पार्टी आलाकमान का फैसला मानेंगे। चन्नी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी उनके नेता हैं और वे उनके साथ जीना—मरना चाहते हैं। इन दावों के बादजुद, चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने समर्थकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिससे संकेत मिलता है कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। इस बैठक को राजा वड़िग के साथ चल रहे टकराव के बीच खुद को मजबूत दिखाने की चन्नी की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली में, चन्नी और रंधावा ने कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात की, लेकिन चन्नी की राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो सकी। चन्नी चाहते थे कि राहुल गांधी उनसे मिलकर उनकी बात सुनें। पार्टी आलाकमान ने अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए अमरिंदर सिंह राजा वड़िग को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि चन्नी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के नेतृत्व वाले नेताओं का एक घड़ा इस फैसले का विरोध कर रहा है और वड़िग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर चन्नी को राज्य में पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग कर रहा है। इसी बीच, चन्नी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर सारा पंजाब चन्नी नाल (सारा पंजाब चन्नी के साथ) संदेश वाली तस्वीरें साझा की हैं, जो इस अंदरूनी खींचतान को और उज्जगर करती हैं। पंजाब मामलों के कांग्रेस प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल ने राज्य इकाई में गुटबाजी को लेकर अपनी रिपोर्ट भी पार्टी नेतृत्व को सौंपी है। ये सभी घटनाक्रम दर्शाते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व के प्रयासों के बावजूद पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल की स्थिति अभी भी दूर है।

वांगचुक ने कहा- तोड़ देंगे अनशन, पर 20 जुलाई के मार्च को सफल बनाना होगा!

नई दिल्ली(एजेंसी)।सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो पिछले बीस दिनों से जंतर-मंतर पर नीट पेपर लोक के विरोध में शिक्षा मंत्री धर्मदे प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं, अब इसे खत्म करने को राजी हो गए हैं। हालांकि, उन्होंने यह शर्त सरकार के सामने नहीं, बल्कि जनता के सामने रखी है। कहा कि उन आरोपों के लिए तथ्यों की जांच जरूरी है, इसलिए यह जांचने के लिए कि क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था, हाई कोर्ट ही सही मंच है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी लंबित याचिकाओं को संबंधित हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया, और यह स्पष्ट किया कि उसके पूर्व के फैसले को उसमें बनाए न कि अपवादा के साथ पढ़ा जाना चाहिए, न कि किसी अलग कानूनी प्रावधान के तौर पर। बेंच ने यह भी कहा कि बुलडोजर एक्शन के अलग-अलग मामलों में तथ्यों से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए अवमानना की कार्यवाही सही तरीका नहीं है। वरिष्ठ अधिकारकों ने सुनवाई के दौरान विभिन्न मामलों का हवाला दिया, जिसमें सोमाथली सुनिश्चित करना भी शामिल है। उन्होंने लोगों से स्थानीय नेताओं द्वारा बुलडोजर कार्रवाई का आह्वान करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शामिल थी।

वांगचुक ने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि वे केवल अनशन खत्म करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि एक छोटा कदम उठाने के लिए कह रहे हैं, जिसमें मिस्ट्र कॉल करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना भी शामिल है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे अपनी माताओं को साथ



लेकर संसद तक मार्च करें। उन्होंने वादा किया कि यदि यह मार्च कामयाब रहा और मुद्दा सही हाथों में मार्च कर पाना उनकी नजर में कामयाबी होगी। इस अनशन तोड़ देंगे। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं

किया कि वह मार्च की सफलता के लिए क्या पैमाने मानेंगे, जैसे कितनी भीड़ या कितनी दूर तक मार्च कर पाना उनकी नजर में कामयाबी होगी। इस अनिश्चितता के बावजूद, उनका आह्वान जनता के

सहयोग पर केंद्रित है ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके संघर्ष को एक निर्णायक मोड़ मिल सके। अपने अनशन के 19वें दिन तक सोनम वांगचुक का वजन 9 किलो घट गया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर बताया कि बहुत से लोग उनसे अनशन खत्म करने का आग्रह कर रहे हैं। वांगचुक ने स्वीकार किया कि उनका शरीर कमजोर हुआ है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी हालत इतनी खराब नहीं है कि वे 3-4 दिन में मर जाएं। उन्होंने कहा कि वह अपना अनशन तभी खत्म करेंगे जब जनता एकजुटता दिखाएगी। इसी संदर्भ में उन्होंने लोगों से 20 जुलाई के संसद मार्च में बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से माताओं से इस मार्च का नेतृत्व करने की अपील की, यह कहते हुए कि बच्चों के लिए मां के दिल में जो प्यार होता है, वह किसी और के दिल में नहीं होता।

महाराष्ट्र में युवक की गोली मारकर हत्या, शिवसेना पार्षद समेत 16 पर मामला दर्ज

मुंबई, (एजेंसी) । महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने शिवसेना के एक पार्षद और 15 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक यह घटना बुधवार रात कलमनुरी शहर में हुई थी। पुलिस के मुताबिक एक पुराने विवाद को लेकर एक समूह के साथ हुई झड़प में लुकमान सिद्दीकी (38) को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि इस समूह में शिवसेना पार्षद किशोर भालेराव भी शामिल थे। पुलिस ने बताया बाद में गंभीर चोटों के कारण लुकमान की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमले में किन्ती गो़लियां चलाई गईं, इसकी जांच अभी जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि भालेराव और 15 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनकी तलाश जारी है। इस बीच, कांग्रेस सांसद रघुां गायकवाड़ ने इस घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की और राज्य में कानून—व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कानून का शासन खत्म हो गया है। सत्ता की ताकत के साथ गुंडागर्दी को शाही संरक्षण मिला है। सत्ता में बैठे लोगों की छत्रछाया में अपराधी बेखोफ हैं, जबकि आम नागरिक डरे हुए हैं।

पुरी रथ यात्रा में श्रद्धालु की मौत पर सियासी घमासान

–विपक्ष ने सरकार को घेरा, भीड़ प्रबंधन पर उठे सवाल

भुवनेश्वर (एजेंसी)। ओडिशा के पुरी में वार्षिक रथ यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु की कथित भगदड़ में मौत के बाद राज्य सरकार पर मुख्य विपक्षी दलों, बीजू जनता दल और ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) ने निशाना साधा है। ओपीसीसी अध्यक्ष भक्त चरण दास ने मृतक श्रद्धालु अनिल दास के प्रति गहरा दुख व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सतर्क रहने और भीड़ प्रबंधन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने बताया कि क्योइर जिले के निवासी अनिल दास की मौत बड़ा झंडा (ग्रेंड रोड) स्थित मारीचिकोट चौक के पास अत्यधिक भीड़ के कारण दम घुटने से हुई, जहां वह पुलिस बैरिकेड से लगभग 100 फीट दूर अचानक गिर पड़े। उन्हें तुरंत पुरी जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भक्त चरण दास ने इस तरह की घटनाओं के बार-बार होने को गंभीर चिंता का विषय बताया और इसकी गहन समीक्षा की मांग की। उन्होंने घटना को अक्षय्य बताते



हुए आरोप लगाया कि एक श्रद्धालु की मौत हुई है, जबकि 150 से अधिक लोगों को दम घुटने और भीड़ से संबंधित अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इलाज कराना पड़ा। उन्होंने पिछले वर्ष की रथ यात्रा का भी उल्लेख किया, जिसमें भगदड़ के कारण तीन लोगों की मौत हो गई थी। दास ने आरोप लगाया कि अत्यधिक संख्या में कॉइन पास जारी करना और आरएसएस स्वयंसेवकों को प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देना कथित अव्यवस्था के प्रमुख कारणों में से थे। उन्होंने पारंपरिक ताहिया (एक बड़ा और सुगंधित पुष्प मुकुट) के बिना भगवान जगन्नाथ की रथ पर मार्क पहनना, बाहर से आने के बाद हाथों को साबुन और पानी से धोना, खांसी या जुकाम होने पर मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना शामिल है। यदि बढ़ते बीमार हो, तो उन्हें स्कूल या खेलने न भेजें और घर पर उचित वैटिलेशन की व्यवस्था बनाए रखें। घरबाने के बजाय सतर्कता और सावधानी ही इस स्थिति से निपटने का सर्वोत्तम उपाय है।

रथ यात्रा के दौरान भगदड़ की घटनाओं के आरोपों से इनकार किया है, लेकिन घटना में दो श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि की। सरकार के अनुसार, रथ यात्रा के दौरान सात लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से 60 वर्ष से अधिक आयु के एक पुष्प श्रद्धालु की कथित तौर पर दम घुटने के कारण मृत्यु हो गई। इसके अलावा, एक अलग घटना में, 35 वर्ष से अधिक आयु के एक अन्य पुष्प श्रद्धालु की मौत हो गई थी। घटना के बाद, राज्य में धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।



सक्षिप्त समाचार

कांगो के जंगल में मिली नई बंदर प्रजाति : 75 साल में अफ्रीका की पांचवीं खोज



लोमामी, एजेंसी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के लोमामी नेशनल पार्क में रहने वाले काले फर और गुलाबी-नारंगी होंठ वाले दुर्लभ बंदर को वैज्ञानिकों ने नई प्रजाति के रूप में मान्यता दी है। आनुवंशिक अध्ययन, आँड़ियों रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी के आधार पर इसकी पुष्टि की गई। नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम कोलोबस कांगोएन्सिस रखा गया है। इस बंदर को पहली बार 2008 में संरक्षणकर्मियों ने देखा था, लेकिन उस समय केवल धुंधली तस्वीर ही मिल सकी। 2018 में दोबारा दिखने के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, अमेरिका और जर्मनी के वैज्ञानिकों की टीम ने इसका विस्तृत अध्ययन शुरू किया। डीएनए विश्लेषण और अन्य वैज्ञानिक जांच में यह पहले से ज्ञात सभी प्रजातियों से अलग पाया गया। स्थानीय लोग इसे ‘लिववेली’ नाम से जानते हैं। 52 गांवों में किए गए सर्वे के दौरान केवल आठ गांवों के लोगों ने इसे देखने की पुष्टि की। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 75 वर्षों में अफ्रीका में खोजी गई यह पांचवीं नई बंदर प्रजाति है। यह कोलोबस समूह का सदस्य है, जिनमें अंगूठा नहीं होता और जो जंगलों में बीजों के प्रसार तथा वन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला, दो पुलिसकर्मियों की मौत, 34 जख्मी

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान का अशांत खेबर पख्तूनख्वा प्रांत एक बार फिर दहल उठा है। बुधवार को यहां दो अलग-अलग इलाकों में बड़े आतंकी हमले हुए। पहले हमले में आतंकीयों ने बन्नु जिले के मिरियान पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया। वे बारूद से भरी गाड़ी लेकर थाने में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुरक्षा बलों ने मुस्तेदी दिखाई और गाड़ी को रास्ते में ही गोलियों से उड़ा दिया। इस मुठभेड़ में चार हमलावर मारे गए। हालांकि, इस भोषण धमाके और गोलीबारी में 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें से 10 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। दूसरा हमला लोअर दीर जिले के लदाम टॉप इलाके में हुआ। यहां आतंकियों ने पहले से घात लगाकर पुलिस के एक काफिले पर धावा बोल दिया। आतंकियों ने पुलिस की गाड़ियों पर हेंड ग्रेनेड फेंके और फिर अंधाधुंध कार्रवाई शुरू कर दी। इस अचानक हुए हमले में 2 पुलिसकर्मी मौके पर ही बलिदान हो गए, जबकि 19 अन्य जवान घायल हुए हैं। उपद्रवियों ने पुलिस की दो गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दोनों ही घटनाओं के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और हमलावरों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

लीबिया तट के पास प्रवासियों से भरी नाव पलटी, 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका, 10 ने तैरकर बचाई जान

त्रिपोली, एजेंसी। उत्तर अफ्रीकी देश लीबिया के पूर्वी तट के पास एक बार फिर बड़ा समुद्री हादसा हुआ है। यूरोप जा रहे करीब 60 प्रवासियों से भरी एक नाव समुद्र में पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 50 प्रवासियों के मारे जाने या लापता होने की आशंका है। लापता लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तटरक्षक बलों के मुताबिक, यह हादसा मंगलवार को टोब्रुक शहर के पास बारदा द्वीप के करीब हुआ। नाव डूबने के बाद 10 प्रवासी किसी तरह तैरकर द्वीप तट पहुंचे और अपनी जान बचाई। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अफ्रीका और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और गरीबी से तंग आकर लोग बेहतर ज़िंदगी की तलाश में यूरोप भाग रहे हैं। साल 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के तख्तापलट के बाद से लीबिया में अराजकता का माहौल है। इसके बावजूद यह देश प्रवासियों के लिए यूरोप जाने का सबसे बड़ा ट्रांजिट पॉइंट बना हुआ है। मानव तस्क़र अवसर प्रवासियों को असुरक्षित और छोटी नावों में दूस-दूस कर भर देते हैं, जिससे ऐसे हादसे आम हो गए हैं। पिछले महीने भी लीबिया तट पर 51 लोग लापता हो गए थे। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल 1 जनवरी से 16 मई के बीच ही इस समुद्री रास्ते पर 800 से ज्यादा प्रवासी अपनी जान गंवा चुके हैं या लापता हुए हैं।

फिर शुरू हुआ ट्रेड वॉर?: यूएस ने ब्राजील पर लगाया 25% टैरिफ, लूला सरकार ने जताया विरोध, कहा- ये नियम का उल्लंघन

वाशिंगटन , एजेंसी। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूटीआर) ने ब्राजील से आयातित कुछ वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की है। यह फैसला व्यापारिक प्रथाओं की एक साल लंबी जांच के बाद, 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत लिया गया है। राष्ट्रपति सिल्व्वा ने क्या कहा- राष्ट्रपति लूला दा सिल्व्वा के नेतृत्व वाली ब्राजील सरकार ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए इस कदम को द्विपक्षीय संबंधों में एक दुःखद मील का पथर और बहुपक्षीय व्यापार नियमों का उल्लंघन बताया।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ग्रीर ने क्या कहा- अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर ने गुरुवार को कहा, ‘व्यापक सार्वजनिक सुनवाई और टिप्पणियों के साथ-

साथ ब्राजील के अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की। इसके बाद, आज अमेरिकी व्यापार विभाग 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत ब्राजील की कुछ वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाकर कार्रवाई कर रहा है।’

अमेरिका ने ब्राजील पर क्यांों लगाया टैरिफ: यह कार्रवाई तब हुई है जब अमेरिका ने यह निष्कर्ष निकाला कि ब्राजील की कई व्यापार नीतियां अनुचित और भेदभावपूर्ण हैं, जो अमेरिकी व्यवसायों और श्रमिकों की प्रतिस्पर्धी स्थिति को काफी हद तक बाधित करती हैं।

अमेरिकी व्यापार मंत्रालय की जांच में क्या पाया गया है : अमेरिकी व्यापार मंत्रालय की जांच के बाद पाया गया कि डिजिटल व्यापार और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान

अमेरिकी सेना ने ईरानी ठिकानों पर 90 मिनट तक जारी रखा हमला

वाशिंगटन , एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच हमलों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने गुरुवार सुबह (भारतीय समयानुसार) कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर स्थानीय समयानुसार बुधवार को 90 मिनट तक तबाड़ती हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमले की जानकारी साझा करते हुए लिखा, ‘दोपहर 3 बजे (स्थानीय समय) पर अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ हमलों की दूसरी लहर के लिए ऑपरेशन शुरू किया। हमले ईरानी सैन्य क्षमताओं को टारगेट कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल होमुंज स्ट्रेट से आसानी से गुजरने वाले जहाजों को धमकाने के लिए किया जाता है।’ न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को (स्थानीय समय) अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा था कि उसने सुबह 6 बजे ईस्टर्न टाइम पर ईरान के खिलाफ हमलों का दौर शुरू किया था।

अमेरिका ने ईरान पर 90 मिनट तक हमलों का राउंड जारी रखा। इस दौरान अमेरिकी सेना ने ग्रेटर टुंब आइलैंड में कोस्टल डिफेंस सिस्टम और कूज मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च साइट्स पर सटीक हमले किए।

हालांकि, ईरान ने भी अमेरिकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। ईरान ख़ाड़ी देशों में अमेरिकी संपत्तियों और बेसों को निशाना बना रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स



(आईआरजीसी) ने बुधवार को कहा कि उसने बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए, जिसमें उनके सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरक्राफ्ट शेल्टर, खास कमांड सेंटर और रणनीतिक ड्रोन पर हमला किया गया।

आईआरजीसी ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के नए हमले के जवाब में जॉर्डन के अल-अजराक में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया। ईरान की आधिकारिक इस्लामिक रिपब्लिक

न्यूज एजेंसी (आईआरएनए) ने बताया कि हमले में वे शेल्टर तबाह हो गए जिनमें यूएस एफ-15, एफ-16 और एफ-35 फाइटर जेट और बेस पर

हांगकांग में 5 बुकसेलर्स गिरफ्तार: सरकार विरोधी ‘देशद्रोही’ किताबें बेचने का आरोप



हांगकांग , एजेंसी। हांगकांग में सरकार विरोधी ‘देशद्रोही’ सामग्री वाली किताबें बेचने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा पुलिस ने पांच बुकसेलर्स को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने दो बुकस्टोर्स पर छापेमारी कर बड़ी संख्या में किताबें जब्त की हैं। अधिकारियों का दावा है कि इन पुस्तकों में हांगकांग सरकार, न्यायपालिका और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के खिलाफ नफरत भड़काने वाली सामग्री थी। सरकार के मुताबिक, कर्टम विभाग ने विदेश से आई कथित देशद्रोही किताबों की एक खेप पकड़ी थी। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा पुलिस

ने जांच शुरू की और दो बुकस्टोर्स में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 37 और 57 साल के दो पुरुष तथा 30 से 59 साल की तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि दुकानों में ऐसी किताबें प्रदर्शित और बेची जा रही थीं, जिनका उद्देश्य सरकार और सरकारी संस्थानों के खिलाफ लोगों को उकसाना था। तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में कथित देशद्रोही सामग्री वाली किताबें भी जब्त की गईं। स्थानीय मीडिया के अनुसार, कार्रवाई ‘हैव अ नाइस स्टे’ और ‘ग्रीनफील्ड बुकस्टोर’ में हुई।

तड़पकर नहीं, गरिमा से विदा होंगे मरीज: फ्रांस में इच्छामृत्यु को हरी झंडी, नए कानून में क्या है खास?

पेरिस, एजेंसी। फ्रांस में वर्षों से जारी लंबी नैतिक और कानूनी बहस के बाद आखिरकार इतिहास रच दिया गया है। फ्रांस की संसद के निचले सदन ‘नेशनल असेंबली’ ने इच्छामृत्यु (असिस्टेड डाइंग) से जुड़े एक ऐतिहासिक बिल को अंतिम मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत अब असाध्य बीमारियों से जूझ रहे वयस्क मरीजों को खुद अपनी मर्जी से मौत चुनने के लिए घातक दवाएं लेने की अनुमति होगी। राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों की ओर से तीन साल पहले घोषित किए गए इस कानून पर संसद में 241 के मुकाबले 291 वोटों से मुहर लगी।

क्या मरीजों को दर्द से मुक्ति दिलाएगा यह नया कानून : फ्रांस

एक पारंपरिक रूप से कैथोलिक देश रहा है, जहां जीवन के अंतिम क्षणों और इच्छामृत्यु को लेकर लंबे समय से कानूनी, चिकित्सा, नैतिक और धार्मिक सवाल उठते रहे हैं। अब तक वहां डॉक्टरों को केवल मरणासन्न मरीजों को बेहोश रखने की अनुमति थी, लेकिन वे इच्छामृत्यु नहीं दे सकते थे। इस वजह से कई फ्रांसीसी नागरिक इच्छामृत्यु के लिए पड़ोसी देशों का रुख करते थे। इस नए कानून के तहत मरीजों को सख्त शर्तों के साथ चिकित्सीय रूप से सहायता प्राप्त आत्महत्या (मेडिकली असिस्टेड सुसाइड) की अनुमति होगी। इसके तहत मरीज डॉक्टर की ओर से दी गई घातव दवाई का खुद ही सेवन कर सकेंगे। फ्रांस के इस नए कानून की नौ

सबसे बड़ी बातें इच्छामृत्यु के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। उसका फ्रांस का नागरिक या कानूनी निवासी होना अनिवार्य है। मरीज को ऐसी गंभीर और लाइलाज बीमारी होनी चाहिए जो जानलेवा हो और वह असहनीय दर्द से गुजर रहा हो। अल्जाइमर जैसे न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों से पीड़ित लोग इसके पात्र नहीं होंगे। आवेदन की शुरुआत मरीज को खुद करनी होगी। मीडिकल टीम 15 दिनों के भीतर इसकी समीक्षा करेगी और मरीज को सोचने के लिए कम से कम 2 दिन का समय दिया जाएगा। क्या सांविधानिक चुनौतियों को पार कर पाएगा यह कानून? इस कानून को लेकर फ्रांस में विरोध के स्वर भी तेज हैं।

रहिवादी बहुमत वाले ऊपरी सदन (सीनेट) ने इस बिल को खारिज कर दिया था, लेकिन फ्रांस की विधायी व्यवस्था के अनुसार निचले सदन का फैसला अंतिम माना जाता है। अब सीनेट के अध्यक्ष जेराई लाचर और प्रधानमंत्री सेबैस्टियन लेकोर्नू ने इस बिल को ‘सांविधानिक परिषद’ के पास भेजने की घोषणा की है। यह परिषद एक महीने के भीतर यह जांच करेगी कि कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। इसके बाद ही यह देश में प्रभावी रूप से लागू होगा। विरोधी संगठन ‘अलायंस वीटा’ का तर्क है कि मौत को समाधान के रूप में पेश करना मानवीय गरिमा के खिलाफ है और इससे बुजुर्गों व विकलांगों पर दबाव बढ़ेगा।

प्रास की और अमेरिकी चिंताओं के समाधान की तलाश में ब्राजील सरकार के साथ गहन बातचीत की। ग्रीर ने कहा, ‘अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ अमेरिकी आर्थिक हितों की रक्षा करना राष्ट्रपति ट्रंप की ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतियों का आधार है। चाहे वह राजनीतिक भाषण पर सेंसरशिप लगाने से इनकार करने पर अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों को दंडित करना हो, भ्रष्टाचार विरोधी प्रवर्तन में ढिलाई बरतना हो, या ब्राजील के किसानों को अमेरिकी किसानों पर लाभ प्राप्त करने के लिए अवैध रूप से काटी गई भूमि का दोहन करने की अनुमति देना हो, ब्राजील की अनुचित व्यापार प्रथाओं ने अमेरिकी श्रमिकों और उत्पादकों को 21 करोड़ से

अधिक उपभोक्ताओं वाले इस महत्वपूर्ण बाजार तक पहुंचने से रोक दिया है। विदेश मंत्री रुबियो ने क्या कहा-अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि आज राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय को अधिकांश ब्राज़ीलियाई आयात पर 25% टैरिफ लगाने का निर्देश दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया? राष्ट्रपति लूला और उनकी सरकार ने अमेरिका के साथ सद्भावना से बातचीत नहीं की है।' राष्ट्रपति सचिवालय के सामाजिक संके बयान में, ब्राजील ने व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 को लागू करने के अमेरिकी व्यापार मंत्रालय के निर्णय को अस्वीकार कर दिया।

चीन के गुआंगशी में बाढ़ से 39 लोगों की मौत, नौ लापता



बीजिंग , एजेंसी। चीन के गुआंगशी में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से तबाही मची है। अब तक इस क्षेत्र में 39 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 अन्य लोग लापता हैं। चीनी अधिकारियों ने गुरुवार को बाढ़ के हालातों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बाढ़ नियंत्रण और आपदा राहत पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरने वालों में क्षेत्रीय राजधानी नाननिंग में एक बड़े डैम के टूटने से हुई मौतें भी शामिल हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, मंगलवार को चीन के ज़िलिन प्रांत में भारी बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ को देखते हुए अधिकारियों ने आपातकालीन बाढ़ प्रतिक्रिया स्तर को लेवल-4 से बढ़ाकर लेवल-3 कर दिया।

टाइफून बाबी के प्रभाव से ज़िलिन में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते सोंगहुआ नदी के ज़िलिन खंड में इस साल की पहली बड़ी बाढ़ दर्ज की गई है। मेइहे नदी, जो हुइफा नदी की एक सहायक नदी है, में जल स्तर

हाइड्रोलॉजिकल रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। अनुमान है कि पूरी हुइफा नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर चला जाएगा। साथ ही, नदियों में बाढ़, पहाड़ी क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड, भूस्खलन जैसी भू-वैज्ञानिक आपदाओं, छोटे और मध्यम आकार के डैम में आपात स्थिति और शहरों में जलभराव का खतरा भी बना हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, बाढ़ नियंत्रण की स्थिति अभी भी गंभीर और जटिल बनी हुई है। इसी बीच, चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि शुक्रवार तक उत्तर-पश्चिम चीन के पूर्वी हिस्सों में हल्की से भारी बारिश का अनुमान है। साथ ही मध्य शानक्सी प्रांत और मध्य व दक्षिणी शानक्सी प्रांत के कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।

इस दौरान येलो नदी और उसकी कई सहायक नदियों (वेइहे, फेनहे और चिनहे नदियां) में जलस्तर बढ़ने की संभावना है।

पीएम मेलोनी ने पाकिस्तानी मूल की लड़की की हत्या के मामले में कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बोलीं- ‘महिलाओं की आजादी नकारना मंजूर नहीं’

रोम , एजेंसी। इटली में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो कथित सांस्कृतिक या धार्मिक वजहों के नाम पर एक महिला की आजादी, उनका सम्मान और उनके अस्तित्व को नकारने की मंशा रखते हैं। इसका ताजा उदाहरण पाकिस्तान मूल की 18 साल की समन अब्बास की हत्या के मामले में कोर्ट के फैसले के दौरान देखने को मिला। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी इस मामले में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने पाकिस्तान मूल की समन अब्बास की उसके माता-पिता द्वारा की गई हत्या के मामले में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मेलोनी ने लिखा, ‘समन अब्बास की हत्या के आखिरी फैसले के साथ, एक दर्दनाक कानूनी कहानी खत्म हो गई है। इटली में पाकिस्तानी मूल की एक जवान लड़की समन को उसके



माता-पिता और कुछ रिश्तेदारों ने मार डाला, क्योंकि उसने जबरदस्ती शादी का विरोध किया था और अपना भविष्य खुद चुनने के अपने अधिकार पर जोर दिया था।' उन्होंने लिखा कि कोई भी फैसला उसकी जिंदगी वापस नहीं ला सकता, लेकिन यह सही है कि इस जुर्म के लिए जिम्मेदार लोगों को दोषी ठहराया गया है। प्रधानमंत्री मेलोनी ने शख्त हिदायत देते हुए कहा, ‘इटली में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो तथाकथित सांस्कृतिक या धार्मिक वजहों के नाम पर एक महिला की आजादी,

इज्जत और जिंदगी को नकारने की हिम्मत करते हैं। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता और जिनसे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। मेरी संवेदनाएं समन के साथ हैं। भगवान उन्हें शांति दे। बता दें, समन अब्बास इटली में रहने वाली 18 साल की पाकिस्तानी मूल की लड़की थी।

समन के परिवार ने 2021 में उसकी ऑनर किलिंग (सम्मान के नाम पर हत्या) कर दी थी। मुक्तिका के परिवार ने पाकिस्तान में उसकी मर्जी के बिना शादी तय कर दी। समन को ये मंजूर नहीं था और वह

लगातार इस शादी का विरोध करती रही। इस विरोध का अंजांम उसकी मौत थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, समन के परिवार ने उसकी शादी पाकिस्तान में उसके चचेरे भाई के साथ तय की थी। इस दौरान समन नाबालिग थीं और उन्होंने शादी से इनकार करने के बाद इटली में सोशल सर्विस डिपार्टमेंट से मदद मांगी। नवंबर 2020 में उन्हें एक शेल्टर होम भेज दिया गया था। उन्होंने अपने माता-पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन 11 अप्रैल 2021 को वह दोबारा अपने परिवार के पास लौट गईं। साइप्रस मेल की रिपोर्ट के अनुसार, समन अप्रैल 2021 से लापता थी। पुलिस ने घर के पास वाले सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें पांच लोग घर से फावड़े, लोहे की रॉड और एक बाल्टी लेकर जाते हुए दिखाई दिए और करीब छई घंटे बाद वे वापस लौटे।

अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स पर हमला



यूटा , एजेंसी। अमेरिका के वेली फेयर मॉल में दोपहर में हुए एक क्रूर हमले में भारतीय मूल के एक मुस्लिम कर्मचारी को चाकू के कई धावों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में जारी किए गए अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, संदिग्ध ने पुलिस के सामने साफ रूप से कबूल किया है कि वह पीड़ित की हत्या उसके इस्लामी धर्म के कारण करने का प्रयास कर रहा था।

क्या है पूरा मामला : संदिग्ध की पहचान 48 वर्षीय पीटर माइकल लार्सन के रूप में हुई है। आरोप है कि उसने सोमवार शाम को एक मॉल के स्टॉल पर पीड़ित सैयद सोहेल उद्दीन से संपर्क किया। हमला करने से पहले, लार्सन ने कर्मचारी से उसकी पहचान के बारे में पूछताछ की।

लड़ाई कैसे शुरू हुई : लूना नुनेज, जो बाद में अस्पताल में पीड़ित से मिलने गई थीं। उनके अनुसार, बातचीत तनावपूर्ण सवालों से शुरू हुई। लार्सन ने कर्मचारी से पूछा, ‘वह कहाँ से है, उसका नाम क्या है और क्या वह मुसलमान है।’ झगड़े के तुरंत बाद, लार्सन ने चाकू निकाला और उस व्यक्ति पर बार-बार वार करने

लगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, हिंसा तभी रुकी जब मॉल में मौजूद साहसी लोगों ने मौके पर पहुंचकर लार्सन को जमीन पर गिरा दिया और उसका हथियार छीन लिया। **पीड़ित के दोस्त ने क्या बताया :** भारतीय मूल के उद्दीन इस समय जीवन-मरण के बीच जूझ रहे हैं। उद्दीन के बॉस और करीबी पारिवारिक मित्र अदनाम मोहम्मद ने चोटों की भयावहता का बारे में बताया कि उद्दीन के पूरे शरीर पर घाव हैं। एक आपातकालीन टीम उनके दिल की स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है। अपने मित्र के बच जाने पर मोहम्मद ने कहा कि उद्दीन का जीवित रहना एक चमत्कार है।

लोगों को ऑनलाइन नफरत भरे संदेश मिल रहे हैं : न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, हमले के बाद मोहम्मद ने अपनी सुरक्षा की भावना पर पड़े गहरे भावनात्मक आघात को व्यक्त किया। खासकर हमले के बाद के हालात देखने और ऑनलाइन नफरत भरे संदेशों का सामना करने के बाद। मोहम्मद ने बताया, ‘मैं एक पिता हूं, और मुझे अपने बच्चों के लिए यह सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है।’



सूरजमुखी के बीज और नट्स में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई के साथ-साथ जब अन्य पोषक तत्वों का सेवन किया जाता है तो इससे उम्र के होने वाली आंखों की कमजोरी को काफी हद तक रोका जा सकता है।

आंखें यकीनन व्यक्ति के शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है। छोटी सी आंखों की मदद से आप इतने बड़े संसार को देख पाते हैं। लेकिन आज के समय में जब लोग अपना ज्यादातर समय स्क्रीन पर बिताते हैं तो उसके कारण आंखों को काफी नुकसान पहुंचता है। यही कारण है कि बेहद कम उम्र में ही लोगों की आंखों पर चश्मा लग जाता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक अपनी आंखों की रोशनी को यूं ही बनाए रखना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपने आहार पर भी फोकस करें। तो चलिए आज हम आपको उन आहार के बारे में बता रहे हैं जो आपकी आंखों के लिए काफी अच्छा है—

कच्ची लाल शिमला मिर्च
शिमलामिर्च में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है। यह आपकी आंखों की रक्तवाहिकाओं के लिए अच्छा है। वहीं लाल शिमलामिर्च से आपको विटामिन ए और विटामिन ई भी प्राप्त होता है, जो आपकी आंखों को तंदुरुस्त बनाने में मदद करता है।

अपने आहार पर करें फोकस आंखें रहेंगी अच्छी

सूरजमुखी के बीज और नट्स सूरजमुखी के बीज और नट्स में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई के साथ-साथ जब अन्य पोषक तत्वों का सेवन किया जाता है तो इससे उम्र के होने वाली आंखों की कमजोरी को काफी हद तक रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, यह मोतियाबिंद को रोकने में भी मददगार है। वैसे आप नट्स के साथ-साथ हेजलनट्स, मूंगफली और पीनटबटर का सेवन करके भी विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में पा सकते हैं।

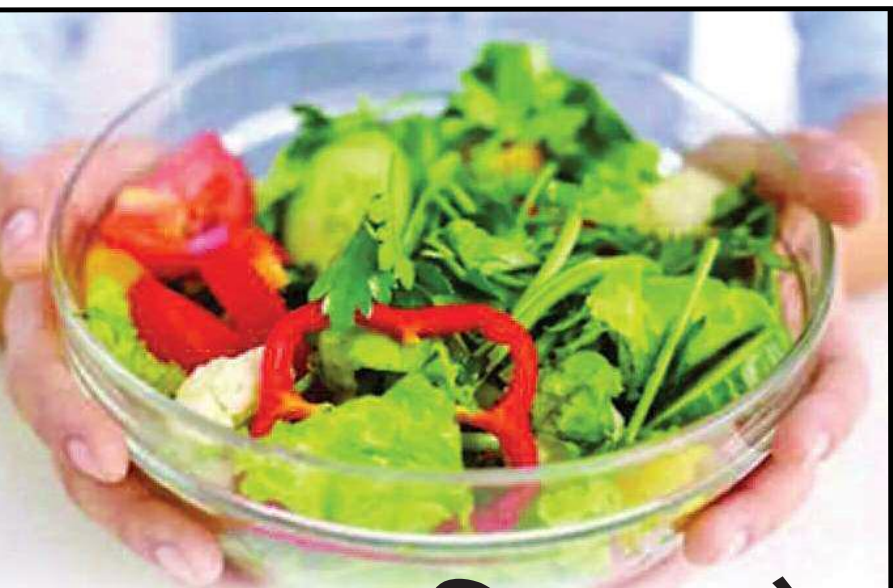
हरी पत्तेदार सब्जियां
केल, पालक व अन्य हरी पत्तेदार

सब्जियों में विटामिन सी और ई की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इतना ही नहीं, इनमें कैरोटिनॉयड्स ल्यूटिन और जैक्सैथिन भी होता है। साथ ही इनमें पाया जाने वाला विटामिन ए लंबे समय में आंखों की बीमारियों से भी व्यक्ति की रक्षा करता है।

सैल्मन

आपकी आंखों के रेटिना को सही काम करने के लिए दो प्रकार के ओमेगा-3 फैटी एसिड की आवश्यकता होती है— डीएचए और ईपीए। आप फैटी फिश, जैसे सैल्मन, ट्यूना और ट्राउट व अन्य कई सी-फूड में इसे पा सकते हैं। वहीं इन

फैटी एसिड के कम होने पर लोगों को डार्ड आंखों की समस्या का सामना करना पड़ता है। शकरकंद में बीटा-कैरोटीन उच्च मात्रा में पाया जाता है, जो वास्तव में विटामिन ए का ही एक रूप है। यह आपके नाइट विजन को बेहतर बनाता है। वहीं एक शकरकंद से आपको दैनिक आवश्यकता की आधे से ज्यादा विटामिन सी की प्राप्ति होती है, वहीं इसमें कुछ मात्रा में विटामिन ई भी पाया जाता है। वैसे शकरकंद के अलावा गाजर, कैटालुप, आम और खुबानी में भी बीटा-कैरोटीन उच्च मात्रा में होता है।



लंच या डिनर से आधा घंटा पहले खाएं सलाद

सलाद लगभग हर जगह खाई जाती है। हा इससे रूप अलग-अलग हो सकते हैं। कहीं उबालकर तो कहीं भूनकर हमारे यहां सलाद को ताजा सब्जियों जैसे खीरा, टमाटर, मूली, गाजर और कच्ची प्याज आदि से तैयार किया जाता है। क्योंकि यह सलाद कच्चा होता है और प्याज के अलावा ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं, जिन्हें अलग से खाना जा सकता है। इसलिए हमारे यहां भोजन के साथ सलाद खाने को वर्जित माना गया है। ये और बात है कि यंग जनरेशन को अपनी ही परंपराओं को बारे में जरा कम पता है!

सलाद खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यह बात हम सभी जानते हैं। इसलिए फलों से लेकर सब्जियों और स्पाउट्स की सलाद हमारे यहां खूब खाई जाती है। जबकि कुछ लोग या कहिए कि सलाद के शौकीन ज्यादातर लोग अपने शरीर को सलाद का पूरा पोषण नहीं दे पाते। क्योंकि उन्हें सलाद खाने का सही तरीका ही नहीं पता है।

सलाद खाने का सही समय
सलाद हमेशा ही भोजन से पहले खानी चाहिए। जबकि लगभग 90 प्रतिशत लोग सलाद का सेवन खाने के साथ करते हैं। इससे उनके शरीर को सलाद का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। बल्कि कई बार डायजेशन से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं।

इतनी देर पहले खाएं

जब आपको भूख लगी हो या आपने जो भी अपने लंच और डिनर का समय तय कर रखा है, उससे कम से कम आधा घंटा पहले सलाद खा लें। इसके बाद लंच या डिनर लें। इससे आपके शरीर को पूरा पोषण मिलेगा और ओवर इटिंग से छुटकारा भी।



वेट रहता है कंट्रोल

सलाद अगर सही तरीके से खाई जाए तो इससे वेट को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। यह हमारे पाचनतंत्र को सही रखती है और पेट साफ करने में मदद करती है। यह शरीर में एक्सट्रा फैट जमा होने से रोकती है और हमें ओवर इटिंग से भी बचाती है। जिससे हमारा वजन नियंत्रित रहता है।

सलाद के तरीके

आमतौर पर सलाद दो तरीके से बनाई जाती है। पहला तरीका का कच्चा सलाद, जिसमें आप फल और सब्जियों को काटकर मिक्स करते हैं और मसाला छिड़ककर सैलेड तैयार कर लेते हैं। जबकि दूसरा तरीका है वॉइल करके सैलेड तैयार करना। इसमें सब्जियों को उबालकर उनका पानी अलग करके सलाद तैयार किया जाता है। लेकिन आप कोई-सी भी सलाद खाएं आपको इसे फुल मील के साथ नहीं खाना है।

क्यों ना खाएं भोजन संग सलाद
सलाद चाहे जैसे भी बनाई गई हो। अगर यह फलों या सब्जियों से तैयार की गई है तो आमतौर पर इनकी प्रकृति टैंडी होती है (हम यहां किसी रेसिपी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हर तरह के भोजन को एक साथ डिस्क्राइब या कैपेयर नहीं किया जा सकता।) जबकि पका हुआ भोजन गर्म होता है। ऐसे में ठंडे गर्म का संगम, सिर्फ शरीर ही नहीं दांतों को भी हानि पहुंचाता है।

पाचन में अधिक समय

सलाद तापमान में टैंडी होती है और भोजन तापमान में गर्म होता है। जब कच्चा और पका हुआ भोजन एक साथ खाया जाता है तो इससे हमारे पाचनतंत्र पर अधिक दबाव पड़ता है। क्योंकि इसे पचाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है। साथ ही ऐसा भोजन डायजैस्ट करने में अधिक समय भी लगता है, जिससे कई बार डायजैस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है।



अश्वगंधा के जरिये कम किया जा सकता है मोटापा

दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा मिला कर पीने से दूर हो जाता है मोटापा, जानें कैसे करता है कामजोड़ी बूटियों का आयुर्वेद में बहुत महत्व है। इनमें कई प्रकार के औषधीय गुण पाये जाते हैं जो बीमारियों को ठीक करने में मदद करती हैं और शरीर को निरोगी बनाए रखती हैं। अश्वगंधा एक ऐसी ही जड़ी बूटी है जो न सिर्फ स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करती है बल्कि वजन घटाने में भी बहुत प्रभावी होती है। अश्वगंधा का उपयोग न सिर्फ आयुर्वेद बल्कि यूनानी, सिद्ध, अफ्रीकन और होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति में भी किया जाता है। अश्वगंधा अनिद्रा, चिंता, डिप्रेशन, यौन समस्याएं, कमजोरी और अर्थराइटिस जैसे रोगों को इलाज में उपयोगी है। इसके अलावा अतिरिक्त फैट को बर्न करने में भी अश्वगंधा बहुत फायदेमंद है। आइये जानते हैं वजन घटाने में अश्वगंधा के फायदे। तो अगर आप नेचुरल तरीके से वजन घटाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अश्वगंधा का प्रयोग जरूर करना चाहिये।

अश्वगंधा का सेवन कैसे करें

वैसे आपको बाजार में अश्वगंधा कैप्सूल के रूप में मिल जाएगा। लेकिन अश्वगंधा पाउडर अधिक फायदेमंद होता है। इसे लेने का तरीका बेहद आसान है। एक गिलास गुनगुने दूध में एक चम्मच अश्वगंधा पावडर और शहद मिलाकर रोजाना सेवन करने से मेटाबोलिज्म और पाचन बेहतर होता है। आप चाहें तो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिये इसमें इलायची पावडर मिक्स कर सकते हैं। इससे मेटाबोलिज्म तो बढ़ेगा ही साथ में पाचन भी मजबूत रहेगा।

सुस्त पड़े मेटाबोलिज्म को बढ़ाएं

अश्वगंधा हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करती है, जिससे शरीर में खाना अच्छी तरह से हजम होता है और मेटाबोलिज्म बढ़ता है। यह फैट को जल्दी जल्दी बर्न करने में मदद करती है। अगर आप घंटों जिम में एक्सरसाइज करते हैं और स्लो मेटाबोलिज्म की वजह से मोटापा कम नहीं हो पा रहा है तो आज से ही अश्वगंधा लेना शुरू कर दें। इससे कम समय में ही मोटापा कम हो जाता है।

स्ट्रेस दूर कर घटाएं मोटापा

स्ट्रेस या कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने से मोटापा भी बहुत तेजी से बढ़ता है। नियमित रूप से अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करने से इस हार्मोन को कम करने में मदद मिलती है। कॉर्टिसोल

बढ़ने की वजह से इंसान को बार बार भूख भी लगती है, जिससे मोटापा बढ़ता है। तनाव से मुक्ति मिलते ही पेट की चर्बी घटने लगती है।

मांसपेशियां बनाने में

अश्वगंधा में ऐसे कई तत्व पाये जाते हैं जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। मसल्स मास बढ़ने से शरीर पर चर्बी नहीं जमती और वजन नियंत्रित रहता है।

इम्यूनिटी बढ़ा कर घटाएं मोटापा

अश्वगंधा में एंटी बैक्टीरियल गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम करता है। इसके अलावा यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है जिसके कारण शरीर पर अतिरिक्त वसा जमा नहीं होती है और वजन नियंत्रित रहता है। यही नहीं अगर शरीर में सूजन है तो यह उसको भी कम करती है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं।



पेट और कमर की बढ़ी चर्बी को अश्वगंधा के जरिये कम किया जा सकता है। इसे रोज दूध के साथ पीने से जल्द ही लाभ मिलेगा। इसे पावडर के रूप में या फिर कैप्सूल के रूप में लिया जा सकता है।

वर्कआउट के लिये बढ़ाती है एनर्जी लेवल

अश्वगंधा एंजिनल ग्लैंड और कॉर्टिसोल लेवल को नियंत्रित करता है जिससे तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है। इससे शरीर की एनर्जी बढ़ती है और थकान दूर होती है। ऐसे में जब आप भारी वर्कआउट करते हैं तो अश्वगंधा शरीर को एनर्जी से भर देता है। यही नहीं अश्वगंधा आयरन से भरपूर होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है।

अच्छी नींद लाएं

रात को अगर आप अधूरी नींद लेते हैं तो न तो आपको मोटापा घटेगा और ऊपर से शरीर को तनाव, उच्च रक्त चाप जैसी बीमारियां और घेर लेंगी। रात में सोते वक्त आपको शरीर हारमोन्स को संतुलित करता है और स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ने से रोकता है। इससे मोटापा कम करने में मदद मिलेगी।

ध्यान रखें अश्वगंधा का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। अत्यधिक सेवन से न सिर्फ उल्टियां हो सकती हैं बल्कि पेट गड़बड़ हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर वाले लोग इसे न खाएं। नींद न आने पर अश्वगंधा का इस्तेमाल कुछ हद तक सही है, लेकिन नींद बूलाने के लिए इसका नियमित सेवन नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस प्रकार औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण अश्वगंधा बीमारियों को दूर करने के अलावा वजन कम करने में भी बहुत फायदेमंद है। नियमित एक चम्मच अश्वगंधा पाउडर का सेवन करने से जल्दी की फर्क नजर आता है।

